संक्षेप में

मारुति ने उतारा डिजायर का नया मॉडल

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया ने शुक्रवार को अपनी कॉम्पैक्ट सिडैन डिजायर का नया उन्नत संस्करण पेश किया। दिल्ली के शोरूम में इसकी कीमत 5.89 लाख रुपये से 8.8 लाख रुपये के बीच बताई गई है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इसके मैनुअल संस्करण की कीमत 5.89 लाख रुपये से 8.28 लाख रुपये है जबकि स्वचालित गियर वाले संस्करण की कीमत 7.31 लाख रुपये से 8.8 लाख रुपये तक है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक (विपणन और बिक्री) शंशाक श्रीवास्तव ने कहा, इस श्रेणी में 55 फीसदी से अधिक की बाजार हिस्सेदारी के साथ डिजायर के पास 20 लाख से अधिक ग्राहकों का भरोसा है। इसे ध्यान में रखते हुए नई डिजायर 2020 में नई पीढ़ी के के-सीरीज इंजन है। साथ ही इसकी बाहरी और आंतरिक सज्जा को प्रीमियम बनाया गया है। इसमें देर तक खड़े रहने की स्थिति में गाड़ी के बंद और चालू होने की प्रणाली लगाई गई है। *भाषा*

अदाणी पोर्ट ने डिबेंचर से जुटाए 125 करोड़ रुपये

अदाणी पोर्ट ऐंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजी) ने डिबेंचर जारी कर शुक्रवार को 125 करोड़ रुपये जुटाए। शेयर बाजार को दी जानकरी में कंपनी ने कहा कि उसने सूचीबद्ध, सुरक्षित, भुनाने योग्य, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से आज (शुक्रवार) 125 करोड़ रुपये जुटाए। निजी नियोजन के आधार पर 10,00,000 रुपये अंकित मूल्य के डिबेंचर जारी किए गए। इन डिबेंचरों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया जाएगा। *भाषा*

अभी नहीं बढ़ेंगे साबुन के दाम

जीसीपीएल, आरबी हेल्थ, विप्रो कंज्यूमर केयर, आईटीसी व ज्योति लैब्स नहीं बढ़ाएंगी दाम

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 20 मार्च

साबुन बनाने वाली देश की अधिकतर कंपनियों ने कोरोनावायर के फैलने के मद्देनजर फिलहाल कीमत न बढ़ाने का निर्णय लिया है। गोदरेज कंज्यूमर (जीसीपीएल) के अलावा आरबी हेल्थ (डिटॉल बनाने वाली कंपनी), विप्रो कंज्यूमर केयर (संतूर बनाने वाली कंपनी), आईटीसी (सैवलॉन बनाने वाली कंपनी) और ज्योति लैब्स (मार्गो बनाने वाली कंपनी) फिलहाल कीमत नहीं बढ़ाएंगी। इन कंपनियों के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकतर कंपनियों का कहना है कि कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर फिलहाल साबुन के दाम न बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जीसीपीएल ने कहा कि मौजूदा परिदृश्य में लोगों के बीच बेहतर स्वच्छता आदतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कंपनी ने यह निर्णय लिया है।

जीसीपीएल के मुख्य कार्याधिकारी (भारत एवं सार्क) सुनील कटारिया ने कहा, 'हम इनपुट लागत बढ़ने के कारण कीमत में कुछ वृद्धि करने की योजना बना रहे थे। लेकिन कोविड-19 के फैलने के मद्देनजर फिलहाल हमने वृद्धि योजना को टालने का निर्णय लिया है। अभी हम सभी चैनलों में पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे ग्राहक बेहतर स्वच्छता आदतों को अपनाएं और सुरक्षित रहें।'

ज्योति लैब्स की प्रबंध निदेशक एमआर ज्योति ने भी कहा कि बेहतर स्वच्छता आदत फिलहाल समय की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'हमने करीब एक महीना पहले अपने मार्गो ब्रांड के तहत हैंडवॉश को बाजार में उतारा था। अब ग्राहकों के पास मार्गो ब्रांड के तहत साबुन के अलावा हैंडवॉश का भी विकल्प मौजूद है। हम शुरुआती पेशकश के साथ अपने हैंडवॉश को बाजार में तेजी बढ़ा रहे हैं।'

साबुन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) को भी इस सप्ताह के आरंभ में कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर अपने साबुन पोर्टफोलियो की कीमतों में तेजी की खबरों का सामना करना पड़ा था। हालांकि कंपनी ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया ऐसी कोई बात नहीं है और भारत में इस वायरस के फैलने से पहले जनवरी में साबुन के दाम बढ़ाए गए थे।

एचयूएल के प्रवक्ता ने कहा, 'हमने त्वचा की साफ-सफाई वाले उत्पाद पोर्टफोलियो के तहत कीमत में 5 से 7 फीसदी की वृद्धि की थी जिसके तहत लक्स, लाइफबॉय, डव, हमाम, लिरिल और पियर्स जैसे ब्रांड हैं। यह वृद्धि भारत में कोरोनावायरस के फैलने से काफी पहले की गई थी। नए स्टॉक का उत्पादन जनवरी में शुरू हुआ था। हमने जनवरी के अंत में अपने तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे में भी स्पष्ट किया था कि कीमत में की गई वृद्धि महंगाई के मुकाबले काफी कम थी। एचयूएल द्वारा मुनाफाखोरी संबंधी खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं।'

विश्लेषकों ने कहा कि साबुन विनिर्माताओं ने पाम ऑयल जैसे कच्चे माल की लागत में नरमी के मद्देनजर फिलहाल कीमत न बढ़ाने का निर्णय लिया है। कैलेंडर वर्ष 2020 के आरंभ से अब तक पाम ऑयल की कीमतों में करीब 24 फीसदी की गिरावट आ चुकी है जबकि कच्चे तेल की कीमतों में 59 फीसदी की गिरावट आई है।

इसके अलावा साबुन की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री हाई-डेंसिटी पॉलिथीन (एचडीपीई) की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। कंपनियों की कुल उत्पादन लागत में इसकी हिस्सेदारी 15 से 20 फीसदी होती है।

साबुन कंपनियों का निर्णय

- ग्राहकों को साबुन के लिए फिलहाल नहीं करना पड़ेगा अधिक खर्च
- प्रमुख साबुन विनिर्माताओं ने अभी कीमत न बढ़ाने का निर्णय लिया
- कच्चे तेल और पाम ऑयल की कीमतों में गिरावट से कंपनियों को मदद
- विश्लेषकों ने कहा, कंपनियां अगले कुछ महीनों तक टाल सकती हैं वृद्धि

एस्कॉर्ट्स में 10 फीसदी हिस्सेदारी लेगी कुबोटा

शैली सेठ मोहिले
मुंबई, 20 मार्च

ट्रैक्टर एवं मशीनरी बनाने वाली प्रमुख जापानी कंपनी कुबोटा कॉरपोरेशन ने एस्कॉर्ट्स में 10 फीसदी हिस्सेदारी लेने की तैयारी कर रही है। दोनों कंपनियां इस साझेदारी के जरिये उत्पाद विकास, विनिर्माण एवं सोर्सिंग के लिहाज से अग्रणी वैश्विक कंपनी बनना चाहती हैं। एस्कॉर्ट्स ने आज स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में यह खुलासा किया।

स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, एस्कॉर्ट्स 850 रुपये प्रति शेयर भाव पर कुबोटा को 1,042 करोड़ रुपये के निवेश के लिए तरजीही आधार पर 1.22 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित करेगी। यह भाव गुरुवार के बंद भाव के मुकाबले 48.21 फीसदी अधिक है। एस्कॉर्ट्स बराबर संख्या में एस्कॉर्ट्स बेनिफिट ऐंड वेलफेयर ट्रस्ट की शेयर हिस्सेदारी घटाएगी ताकि कंपनी की शेयर पूंजी को अपरिवर्तित रखा जा सके। इस सौदे के बाद कुबोटा को एस्कॉर्ट्स के बोर्ड में दो गैर-कार्यकारी सदस्यों को नामित करने का अधिकार होगा।

इस तरजीही आवंटन के साथ-साथ एस्कॉर्ट्स भी कुबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी इंडिया में 40 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। यह भारत में कुबोटा की विपणन एवं बिक्री इकाई है। कुबोटा और एस्कॉर्ट्स 60:40 अनुपात में एक संयुक्त उद्यम बनाएगी जिसका नाम एस्कॉर्ट्स कुबोटा इंडिया होगा। संयुक्त उद्यम अपने मौजूदा स्वरूप में कारोबार जारी रखेगा।

एस्कॉर्ट्स के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निखिल नंदा ने कहा कि इस साझेदारी से एस्कॉर्ट्स को नवोन्मेषी समाधान उपलब्ध कराने और लाभप्रद वृद्धि के लिए उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस साझेदारी का उद्देश्य घरेलू एवं निर्यात बाजार के लिए अत्याधुनिक उत्पाद तैयार करने में कुबोटा की आरऐंडडी ताकत का फायदा उठाना, नए बाजारों में ग्राहकों को अपने उत्पादों की पेशकश करना और नई उत्पाद लाइन तैयार करना है।

नंदा ने कहा, 'हम अपनी विनिर्माण विशेषज्ञता और दमदार घरेलू वितरण के साथ-साथ कुबोटा की विशेषज्ञता के जरिये कृषि उपकरण के क्षेत्र में बाजार की अग्रणी कंपनी बनना और खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं।'

कुबोटा जापान के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि निदेशक यूईची किताओ ने कहा कि इस साझेदारी के जरिये दोनों कंपनियां मिलकर भारत एवं अन्य उभरते बाजारों में आपूर्ति करेंगी। इन बाजारों में अत्याधुनिक तकनीकी एवं नए जमाने के ट्रैक्टरों की काफी आवश्यकता है ताकि मशीनीकृत खेती के लिए जबरदस्त मांग को पूरा किया जा सके। किताओ ने कहा, 'कुबोटा और एस्कॉर्ट्स साथ मिलकर संबंधित क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता के साथ ताकत बढ़ाएंगी और नकनीकी नवाचार उत्कृष्टता को बढ़ावा देंगी ताकि एक वैश्विक अग्रणी कंपनी के तौर पर उभर सकें।'

शेयर बाजार में उथल-पुथल के बावजूद एस्कॉर्ट्स के शेयर में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर नैशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 18.55 फीसदी बढ़त के साथ 680 रुपये पर बंद हुआ जबकि बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी 5.83 फीसदी की बढ़त के साथ 8,745.45 अंक पर बंद हुआ।

सौदे की मुख्य बातें

- 10 फीसदी हिस्सेदारी का मूल्य 1,042 करोड़ रुपये
- कुबोटा को तरहीजी आधार पर एस्कॉर्ट्स के 1.22 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे
- इक्विटी शेयर का निर्गम मूल्य 850 रुपये प्रति शेयर रहेगा
- 19 मार्च के बंद भाव के मुकाबले 48.21 फीसदी अधिक मूल्य पर लेनदेन
- भारत में कुबोटा की बिक्री एवं विपणन कंपनी में 40 फीसदी हिस्सेदारी लेगी एस्कॉर्ट्स

जेएलआर ने ब्रिटेन में उत्पादन रोका

एजेंसियां
लंदन, 20 मार्च

टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने शुक्रवार को अपने ब्रिटिश संयंत्रों में उत्पादन अस्थायी तौर पर बंद किए जाने की घोषणा की। जेएलआर ने कोरोनावायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। कोरोनावायरस से ब्रिटेन में अब तक 144 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार निर्माता ने कहा कि उत्पादन रोके जाने का निर्णय अगले सप्ताह से प्रभावी होगा और यह 20 अप्रैल तक लागू रहेगा। जेएलआर ने एक बयान में कहा है, 'एक जिम्मेदार व्यवसाय के तौर पर, जगुआर लैंड रोवर कोरोनावायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एनएचएस और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड से सलाह के आधार पर परिचलन कर रही है और अपने व्यवसाय की निरंतरता सुरक्षित बनाने के लिए नई योजनाओं पर अमल कर रही है।' हालांकि इसकी पुष्टि हो गई है कि भारत और ब्राजील में कंपनी के निर्माण संयंत्र परिचालन में बने हुए हैं और चीन में संयुक्त उपक्रम संयंत्र भी पिछले महीने के अंत में पुन: खुल गया है, क्योंकि वहां हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं।

आईपीएल में देरी से डिज्नी प्लस की शुरुआत में विलंब

सोहिनी दास
मुंबई, 20 मार्च

स्टार ऐंड डिज्नी इंडिया ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्लेटफॉर्म की शुरुआत टाल दी है। इसकी शुरुआत 29 मार्च को होनी थी। कोरोनोवायरस के डर से इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के सत्र में देरी को देखते हुए स्टार ऐंड डिज्नी ने इस ओवर दि टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म की शुरुआत टालने का फैसला किया है।

डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रमुख कॉन्टेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसे पिछले साल नवंबर में लाया गया था और नवीनतम सूचना के अनुसार 10 साल से कम उम्र के बच्चों वाले अमेरिका के कम से कम 50 प्रतिशत परिवार डिज्नी

प्लस की सदस्यता ले चुके हैं।

वाल्ट डिज्नी कंपनी एपीएसी के अध्यक्ष और स्टार ऐंड डिज्नी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर ने एक बयान में कहा है कि हमने हाल ही में घोषणा की थी कि डिज्नी प्लस इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सत्र के आरंभ के साथ हॉटस्टार सेवा के जरिये भारत में शुरुआत करेगी। सत्र में देरी को देखते हुए हमने डिज्नी प्लस की शुरुआत कुछ देर के लिए रोकने का फैसला किया है और जल्द ही इस सेवा के लिए नई संशोधित तिथि की घोषणा करेंगे।

इस मीडिया दिग्गज ने 14 मार्च को एक मीडिया कार्यक्रम में डिज्नी प्लस हॉटस्टार की शुरुआत के संबंध में घोषणा करने की योजना बनाई थी जिसे वायरस के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था।

उद्योग के एक सूत्र ने कहा कि स्टार आईपीएल के साथ भारत में डिज्नी प्लस की शुरुआत करना चाह रही थी। तब उनके दर्शकों की संख्या पहले ही काफी अधिक होती। यह प्रीमियम स्ट्रीमिंग सेवा के लिए सदस्यता अभियान भी चला देती है। अब आईपीएल की किस्मत अधर में लटकने की वजह से डिज्नी प्लस की शुरुआत भी टल गई है।

डिज्नी प्लस भारत में उस वैश्विक ओटीटी प्लेटफॉर्मों की सूची में शामिल होने वाली है जिसकी शुरुआत नेटफ्लिक्स (जनवरी 2016) ने की थी और फिर 2016 में एमेजॉन प्राइम वीडियो तथा अब इस सप्ताह की शुरुआत में डिस्कवरी प्लस भी इस सूची में जुड़ चुकी हैं।

वर्ष 2019 में हॉटस्टार का डाउनलोड आंकड़ा 40 करोड़ पार कर चुका है और मोटे तौर पर इसके तकरीबन 20 करोड़ उपयोगकर्ता हैं।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी, सीईओ ने 58 करोड़ रुपये के शेयर बेचे

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा है कि उसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी वैद्यनाथन ने अपने ईसॉप ऋण को बंद करने के लिए लगभग 58 करोड़ रुपये में 2.75 करोड़ शेयर बेचे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बीएसई को बताया, 'हमें बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी वैद्यनाथन से सूचना मिली है कि उन्होंने 19 मार्च 2020 को 2,75,58,412 शेयर बेचकर लगभग 58 करोड़ रुपये का ईएसओपी (कर्मचारी शेयर विकल्प योजना) लोन चुकाया है।' बैंक ने कहा, 'उन्होंने बताया है कि इस बिक्री के साथ उनका ईसॉप ऋण खत्म हो गया है, और उन्हें भविष्य में कोई भी शेयर बेचने की जरूरत नहीं होगी।' *एजेंसियां*

उद्योग का विदेशी ऋण भुगतान होगा महंगा

देव चटर्जी
मुंबई, 20 मार्च

- कोरोनावायरस, रुपये में गिरावट से कॉरपोरेट नकदी प्रवाह हुआ प्रभावित
- भारतीय कंपनियों को जून तिमाही में 7.5 अरब डॉलर के विदेशी ऋण की अदायगी करनी है
- एयर इंडिया को अगले महीने 13.5 करोड़ डॉलर अदा करना है जबकि भारतीय स्टेट बैंक को 1.2 अरब रुपये का पुनर्भुगतान करना है
- अन्य बड़ी कंपनियों में आरआईएल को अगले महीने 55 करोड़ डॉलर का विदेशी ऋण पुनर्भुगतान करना है

कई भारतीय कंपनियों के विदेशी ऋण की मार्च के अंत तक अथवा उसके बाद होने वाली अदायगी महंगी हो जाएगी। बैंकरों ने चेताया है कि रुपये में गिरावट और कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लगभग सभी कंपनियों का नकदी प्रवाह प्रभावित होगा।

बैंकरों ने कहा कि शीर्ष उद्योग घरानों के कई अरब डॉलर के विदेशी ऋण ऐसे हैं जिनका पुनर्भुगतान मार्च और उसके बाद की तिमाहियों किया जाना है। एक बैंकर ने कहा, 'अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया जनवरी से अब तक करीब 4 फीसदी कमजोर हुआ है। ऐसे में पुनर्भुगतान और पुनर्वित्तपोषण के बीच कंपनी द्वारा कोई भी विकल्प चुनने पर उसे अधिक भुगतान करना पड़ेगा।'

वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेताया है कि यदि बॉन्ड बाजार में चुनौतियां बरकरार रहीं तो कॉरपोरेट नकदी प्रवाह पर गंभीर दबाव दिख सकता है। रेटिंग एजेंसी ने कहा, 'हाल के सप्ताह में निर्गम का अभाव और मुनाफे में जबरदस्त गिरावट की आशंका के कारण कुछ क्षेत्रों में कंपनियों के नकदी प्रवाह पर दबाव दिखेगा। बॉन्ड बाजार में तात्कालिक बंदी को ऊंची रेटिंग वाली कंपनियां झेल सकती हैं और वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोतों को बरकरार रख सकती हैं। जबकि कमजोर नकदी प्रवाह और निकट भविष्य में बॉन्ड अदायगी के साथ कम रेटिंग वाली कंपनियों के लिए जोखिम कहीं अधिक बढ़ जाएगा।'

बैंकरों ने कहा कि कुछ कंपनियां अपने विदेशी ऋण की अदायगी में चूक कर सकती हैं क्योंकि बंदी के कारण बिक्री में गिरावट होने से उनका नकदी प्रवाह प्रभावित हुआ है।

ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय कंपनियों को जून तिमाही में 7.5 अरब डॉलर के विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान करना है। एयर इंडिया को अगले महीने 13.5 करोड़ डॉलर अदा करना है जबकि भारतीय स्टेट बैंक को 1.2 अरब रुपये का पुनर्भुगतान करना है। अन्य बड़ी कंपनियों में आरआईएल को अगले महीने 55 करोड़ डॉलर का विदेशी ऋण पुनर्भुगतान करना है।

वित्तीय अनुसंधान फर्म क्रेडिटसाइट्स ने अपनी एक रिपोर्ट में चेताया है कि वेदांत रिसोर्सेज को अपने डॉलर बॉन्ड के पुनर्भुगतान में नकदी संकट का सामना करना पड़ सकता है। कंपनी का डॉलर बॉन्ड मार्च 2021 तक परिपक्व होने वाला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेल एवं धातु कीमतों में गिरावट और कोरोनावायरस वैश्विक महामारी के कारण वेदांत रिसोर्सेज के बिना जमानत वाले डॉलर बॉन्डधारकों को शून्य रिकवरी होने की आशंका है।

हालांकि वेदांत के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी पहले कभी चूक नहीं की है और उसका दमदार वृद्धि देने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कंपनी ने सभी ऋणधारकों की देनदारी समय पर चुकाती रही है। वेदांत के प्रवक्ता ने कहा, 'वेदांत ने पिछले 15 वर्षों के दौरान 15 फीसदी सीएजीआर के साथ उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है और अब वह अपने विश्वस्तरीय परिसंपत्ति आधार में दमदार वृद्धि के साथ अगले चरण की ओर अग्रसर है।' (साथ में अभिजित लेले)

एचडीएफसी बैंक के शेयर पर चोट

अमेरिका की बर्नस्टीन ने रेटिंग घटाकर अंडरवेट की और लक्षित कीमत करीब आधा कर दी जबकि यूबीएस ने सकारात्मक रुख बरकरार रखा

हंसिनी कार्तिक और समी मोडक
मुंबई, 20 मार्च

एक ओर जहां बाजार में अग्रणी सूचकांकों में 5.75 फीसदी का सुधार दर्ज हुआ, वहीं दूसरी ओर बीएसई सेंसेक्स और सीएनएक्स निफ्टी में शामिल दिग्गज एचडीएफसी बैंक इसका अपवाद रहा। कारोबारी सत्र में बैंक का शेयर 7.85 फीसदी टूटने के बाद अंत में 1.4 फीसदी के नुकसान के साथ बंद हुआ। यह शेयर अमेरिका की बर्नस्टीन की तरफ से प्रकाशित रिसर्च नोट पर प्रतिक्रिया जता रहा था।

हफ्ते के ज्यादातर समय एचडीएफसी बैंक का शेयर दबाव में था, जो बुधवार को गहरा गया जब उसमें एनएसई पर 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई और यह एक दशक में सबसे ज्यादा एकदिवसीय गिरावट थी। उसी रात एचडीएफसी बैंक के अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट्स यानी एडीआर में 11 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई और गुरुवार को भी गिरावट जारी रही जब उसका एडीआर 12 फीसदी और टूटकर 36.4 डॉलर पर बंद हुआ। गुरुवार के बंद भाव पर एचडीएफसी बैंक के एडीआर और उसके देसी शेयर (शुक्रवार के बंद भाव पर आधारित) का अंतर महज 1.7 फीसदी रह गया है, जो एक दशक का निचला स्तर है। विशेषज्ञों ने ये बातें कही है। अंतिम समाचार मिलने तक एचडीएफसी बैंक का एडीआर 36.48 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। एक एडीआर एचडीएफसी बैंक के तीन सामान्य शेयर के बराबर है। बताया जाता है कि बर्नस्टीन की तरफ से जताई गई चिंता से एचडीएफसी बैंक का एडीआर दबाव में रह सकता है। यह नोट 19 मार्च को प्रकाशित हुआ जहां ब्रोकरेज ने बैंक की रेटिंग मार्केट परफॉर्म से घटाकर अंडरपरफॉर्म कर दिया। साथ ही लक्षित कीमत 1,400 रुपये से घटाकर 750 रुपये कर दिया।

चढ़ते बाजार में टूटा एचडीएफसी बैंक

- कारोबारी सत्र में बैंक का शेयर 7.85 फीसदी टूटने के बाद अंत में 1.4 फीसदी के नुकसान के साथ बंद हुआ
- यह शेयर अमेरिका की बर्नस्टीन की तरफ से प्रकाशित रिसर्च नोट पर प्रतिक्रिया जता रहा था
- एचडीएफसी बैंक के एडीआर में भी भारी गिरावट

एचडीएफसी बैंक की रेटिंग में कमी की प्रमुख वजह कोरोनावायरस के कारण मंदी के बीच उस बैंक का असुरक्षित खुदरा कर्ज और प्रबंधन के उत्तराधिकार पर बैंक का रुख है। बर्नस्टीन के विश्लेषक गौतम चुगानी ने कहा, एचडीएफसी बैंक की आय में 24 फीसदी और बैंक की बढ़त की रफ्तार में 36 फीसदी योगदान असुरक्षित कंज्यूमर फाइनैंस का है और असुरक्षित खुदरा कर्ज की हिस्सेदारी बैंक की लोनबुक में 17 फीसदी है।

इसकी तुलना में आईसीआईसीआई बैंक व ऐक्सिस बैंक की लोनबुक में असुरक्षित खुदरा कर्ज की हिस्सेदारी 9 फीसदी है। विश्लेषकों ने बैंक की सहायक एचडीबी फाइनैंशियल सर्विसेज की क्रेडिट गुणवत्ता पर भी चिंता जताई है, जो कमजोर अनौपचारिक क्षेत्र को सेवाएं देती है। विश्लेषक बैंक की उत्तराधिकार योजना के भी आलोचक हैं।

चुगानी ने लिखा है, एचडीएफसी बैंक ने पिछले संकट का निपटान बेहतर तरीके से किया है और विदेशी निवेशकों की पसंदीदा है, लेकिन उत्तराधिकार योजना समस्या वाला क्षेत्र है। उत्तराधिकार प्रक्रिया के असंतोषजनक नतीजे रेटिंग के जोखिम को गई गुना बढ़ाता है।

दिलचस्प रूप से उसी दिन स्विटजरलैंड की यूबीएस की भारतीय इकाई ने एचडीएफसी बैंक को लेकर एक कॉन्फ्रेंस की, ताकि अग्रणी निवेशकों की चिंता दूर की जा सके। यह बैंक के कुछ देसी व विदेशी निवेशकों तक सीमित था। बाद में एक नोट में यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक के शेयर खरीद की सिफारिश की और 12 महीने की लक्षित कीमत 1,480 रुपये पर अपरिवर्तित रखी। सबसे अहम चीज संपत्ति गुणवत्ता को लेकर थी। यूबीएस सिक्योरिटीज के विश्लेषक विशाल गोयल ने कहा, असुरक्षित खुदरा परिसंपत्ति की गुणवत्ता की प्रवृत्ति स्थिर है। 80 फीसदी असुरक्षित कर्ज वेतनभोगी कर्मचारियों ने लिए हैं, जिनमें अच्छी कंपनियों के कर्मी और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अभी पुनर्भुगतान ठीक है और एमएसएमई के विशाखित पोर्टफोलियो के कारण बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता पर ज्यादा असर नहीं होगा। उन्होंने कहा, 70-75 फीसदी एसएमई कर्ज सुरक्षित है। विमानन कंपनी को बैंक का कर्ज काफी कम है और रेस्तरां व हॉस्पिटैलिटी कारोबार भी उसने सीमित उधारी दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने खरीदे 10,000 करोड़ रु. के बॉन्ड

24 व 30 मार्च को और होगी 15-15 हजार करोड़ रुपये के बॉन्ड की खरीद

अनूप रॉय
मुंबई, 20 मार्च

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 10,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे। बैंकिंग नियामक द्वितीयक बाजार से हालांकि 30,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड की और खरीद करेगा। यह खरीद व्यवस्था में नकदी झोंकने के लिए हो रही है ताकि कोरोनावायरस के कारण सुस्ती के बीच बाजार में सामान्य कामकाज होता रहे।

केंद्रीय बैंक को शुक्रवार के ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए 45,049 करोड़ रुपये की बोली मिली, हालांकि आरबीआई ने 10,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे। यह प्रतिक्रिया बताता है कि बाजार को आरबीआई के नकदी के सहारे की दरकार है, जो उसने पूरा करने का वादा किया है।

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ओपन मार्केट परचेज ऑक्शन 20 मार्च को किया गया, जो सकारात्मक रहा। आरबीआई ने कहा, कोरोनावायरस के कारण वित्तीय बाजार के कुछ निश्चित क्षेत्र पर दबाव अभी भी काफी ज्यादा है और वित्तीय स्थिति सख्त बनी हुई है। आरबीआई की कोशिश यह सुनिश्चित करने की है कि बाजार के सभी क्षेत्र पर्याप्त नकदी व टर्नओवर के साथ सामान्य कामकाज करे।

साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि वह दो और ओएमओ का आयोजन करेगा, पहला 24 मार्च को 15,000 करोड़ रुपये का और फिर 30 मार्च को 15,000 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदेगा ताकि और नकदी झोंकी जा सके। पहली नीलामी में खरीदे गए बॉन्ड दिसंबर 2022 और जनवरी 2029 के बीच परिपक्व होंगे।

- ऐसा नहीं है कि बैंकिंग क्षेत्र नकदी की कमी से जूझ रहा है
- वास्तविकता यह है कि व्यवस्था में नकदी अभी 2.93 लाख करोड़ रुपये है

ऐसा नहीं है कि बैंकिंग क्षेत्र नकदी की कमी से जूझ रहा है। वास्तविकता यह है कि व्यवस्था में नकदी अभी 2.93 लाख करोड़ रुपये है। आरबीआई के आंकड़ों से यह जानकारी मिली।

लेकिन बॉन्ड बाजार का प्रतिफल बढ़ा है क्योंकि विदेशी निवेशकों ने सुरक्षित ठिकानों की तलाश में अपना निवेश बेचा है। बॉन्ड के डीलरों ने कहा, ऐसे समय में बॉन्ड बाजार को देसी निवेशकों पर निर्भर रहने की दरकार है जो बॉन्ड में निवेश करने के लिए नकदी का सहारा चाह रहे हों। इसके अलावा आरबीआई के इस कदम से मजबूती में मदद मिलेगी क्योंकि बाजार को संकेत मिल जाएगा कि केंद्रीय बैंक किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए मौजूद है।

इस हफ्ते आरबीआई ने कहा था कि वह लंबी अवधि के रीपो परिचालन (एलटीआरओ) से 1 लाख करोड़ रुपये व्यवस्था में झोंकेगा और डॉलर की अदला-बदली के जरिए डॉलर की लिक्विडिटी में इजाफा होगा, जिसकी शुरुआत 2 अरब डॉलर अदलाबदली से होगी।

25,000 करोड़ रुपये एलटीआरओ का पहला चरण बुधवार को हुआ। तीन साल के एलटीआरओ में कुल 27,096 करोड़ रुपये की बोली मिली। आरबीआई पहले ही अपने पहले ऑपरेशन में एलटीआरओ के जरिये 1 लाख करोड़ रुपये की नकदी झोंक चुका है।

ओएमओ की घोषणा के बाद 10 साल के बॉन्ड का प्रतिफल घट गया। यह प्रतिफल 6.26 फीसदी पर बंद हुआ, जो पिछले बंद स्तर 6.41 फीसदी से नीचे है। डॉलर के मुकाबले रुपया 75.20 पर बंद हुआ, जो पिछले बंद स्तर 74.99 से नीचे है।

इस साल नियुक्ति की रफ्तार धीमी रख सकती हैं आईटी फर्में

फर्मों की तरफ से ऑफर लेटर पा चुके नए ग्रैजुएट की जॉइनिंग की तारीख भी अलग-अलग हो सकती है

देवाशिष महापात्र और नेहा अलावधी
बेंगलूरु/नई दिल्ली, 20 मार्च

कोरोनावायरस के वैश्विक प्रसार के कारण पैदा हुई अनिश्चितता के कारण आईटी सेवा कंपनियों की तरफ से कॉलेज परिसरों से नए इंजीनियरिंग ग्रैजुएट की नियुक्ति में गिरावट हो सकती है। मानव संसाधन क्षेत्र के विशेषज्ञों के मुताबिक, नए ग्रैजुएट की जॉइनिंग की तारीख भी अलग-अलग हो सकती हैं क्योंकि कंपनियां मांग के परिदृश्य का आकलन करने के बाद ही कर्मचारियों को जोड़ सकती हैं।

स्टाफिंग फर्म सीआईईएल एचआर सर्विसेज के सीईओ आदित्य नारायण मिश्रा ने कहा, ऑफर लेटर हासिल कर चुके फ्रेशर्स की नियुक्ति की तारीख में देर का अनुमान है। अगर अमेरिका और यूरोप के उद्योग पर अगले आठ हफ्ते तक असर जारी रहता है तो नियुक्ति पत्र का निरादर भी हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अगले कुछ हफ्ते तक वायरस पर लगाम नहीं कसी जाती तो इंजीनियरिंग ग्रैजुएट की नियुक्ति में 20 से 30 फीसदी की गिरावट हो सकती है।

मांग के अनुमान से देश की चार आईटी कंपनियों ने पिछले साल 50,000 से ज्यादा फ्रेशर्स की नियुक्ति की। नए ग्रैजुएट की नियुक्ति भी ज्यादातर आईटी कंपनियों की इस पहल का हिस्सा था ताकि अपने कर्मचारियों के पिरामिड को सही आकार का बनाया जा सके, जहां मध्यम स्तर के कर्मचारियों की संख्या हाल के वर्षों में ज्यादा हो गई है।

आईटी फर्मों में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मौजूदा वित्त वर्ष में करीब 30,000 नए ग्रैजुएट को जोड़ा है। कंपनी के प्रबंधन ने कहा है कि वह अगले वित्त वर्ष में इस आंकड़े को बढ़ाकर 39,000 करने जा रही है। इसी तरह इन्फोसिस ने इस वित्त वर्ष में 18,000 को नौकरी की पेशकश की है, वहीं विप्रो ने कहा है कि वह इस वित्त वर्ष में करीब 20,000 नए ग्रैजुएट को जोड़ेगी।

पारीख कंसल्टिंग के आईटी आउटसोर्सिंग एडवाइजर और संस्थापक पारीख जैन ने कहा, नए ग्रैजुएट को कंपनी में शामिल करने की तारीख अब अलग-अलग हो सकती है क्योंकि कंपनियां मांग में नरमी के कारण सतर्क हो सकती हैं। ऐसे में यह बैच में हो सकता है। उन्होंने कहा, वास्तविक असर अब अगले साल की नियुक्तियों पर दिखेगा, जो कोरोनावायरस के प्रसार के बीच मांग परिदृश्य पर निर्भर करेगा।

आईटी उद्योग मांग में सुस्ती से दो-चार हो रहा है क्योंकि अमेरिका समेत कई विकसित देशों ने कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने की खातिर सामाजिक दूरी बनाने के लिए अपने प्रतिष्ठानों को बंद करना शुरू कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप आईटी फर्म बड़े सौदे हासिल करने में देरी का सामना कर रही है और रिपोर्ट बताती है कि करीब 3-4 अरब डॉलर के सौदा पर हस्ताक्षर इस महीने टाल दिए गए।

फ्रेशर्स की नियुक्ति मांग के परिदृश्य पर निर्भर करेगी, लेकिन विशेष कर्मियों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार में भी देर हो रही है क्योंकि कंपनियां आमने-सामने साक्षात्कार लेने में सक्षम नहीं हो पा रही।

टीमलीज डिजिटल के प्रमुख (स्पेशलाइज्ड स्टाफिंग) सुनील चेम्मनकोटिल ने कहा, सबसे बड़ा मसला यह है कि भारत की किसी भी कंपनी के पास ई-नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं है, ऐसे में चयन के बाद भी उम्मीदवार कंपनी से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अभी ज्यादातर क्लाइंटों ने अप्रैल के पहले हफ्ते तक ज्वाइनिंग टाल दी है।

मांग में सुस्ती का नियुक्ति पर असर

- मांग के माहौल के मुताबिक फ्रेशर्स की जॉइनिंग की तारीख अलग-अलग हो सकती है
- अगर अमेरिका व यूरोप में स्थिति ठीक नहीं होती तो 2020 में फ्रेशर्स की नियुक्ति 30 फीसदी तक घट सकती है
- मांग में सुधार के अनुमान में पिछले साल कंपनियों ने अच्छी खासी नियुक्ति की थी
- कोरोनावायरस के प्रसार के कारण विशेष कर्मियों की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार टाल दिए गए हैं

छंटनी व वेतन कटौती की आशंका नहीं

पृष्ठ-1 का शेष

पेटीएम के प्रमुख विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट किया कि अपने कर्मचारियों की मदद के लिए वह दो महीने का वेतन नहीं लेंगे। मैरियट के मुख्य कार्याधिकारी आर्ने सोरेनसन ने कहा कोविड-19 के कारण मैरियट और होटल उद्योग पर हुए वित्तीय असर को देखते हुए वह इस साल के बाकी महीने वेतन नहीं लेंगे। साथ ही मैरियट के शीर्ष अधिकारी भी आधा वेतन ही लेंगे।

शीर्ष उद्योगपतियों की तरफ से यह आश्वासन ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले ही इंडिगो ने अपने शीर्ष अधिकारियों के वेतन में कटौती की घोषणा की थी। अपोलो टायर्स के प्रवतकों ओंकार कंवर और नीरज कंवर ने भी शुक्रवार को अपने पारितोषिक में 25 फीसदी कटौती की घोषणा की। गो एयर पहले ही अपने 80 फीसदी विदेशी कर्मचारियों को घर भेज चुकी है।

श्री सीमेंट के प्रबंध निदेशक एचएम बांगुर ने कहा कि इस तरह के मुश्किल दौर में कारोबार के बजाय लोगों की सुरक्षा को अहमियत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, 'हमने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। यह कारोबार, नफा-नुकसान और राजस्व के बारे में बात करने का सही समय नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कारोबार पर ध्यान नहीं होगा लेकिन कोविड-19 का खतरा कम होने के बाद इसे अहमियत मिलेगी।' सूत्रों के मुताबिक इमामी भी आपात योजना को लागू कर रही है जिसमें कर्मचारियों की सुरक्षा, वितरण व्यवस्था जारी रखना और नकदी के मुद्दे शामिल हैं। लेकिन वह कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर विचार नहीं कर रही है। कैडिला हेल्थकेयर के चेयरमैन पंकज पटेल ने कहा कि कंपनी की छंटनी या कर्मचारियों के वेतन में अस्थायी कटौती की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा, 'यह अस्थायी स्थिति है और गुजर जाएगी। कारोबार में नफा और नुकसान दोनों होते हैं। हम संकट की घड़ी में आननफानन में कोई कदम नहीं उठा सकते हैं।' मैरिको के चेयरमैन हर्ष मारीवाला ने कहा कि इस संकट पर कंपनी की प्रतिकिया और छंटनी इस बात पर निर्भर करेगी कि इस क्षेत्र को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, 'उड्डयन और आतिथ्य जैसे उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन क्षेत्रों की कंपनियों के लिए यह अस्तित्व का सवाल है। मुझे नहीं लगता है कि कोई कारोबारी घराना इस बारे में एकतरफा फैसला कर सकता है। सभी कारणों को ध्यान में रखना होगा।' लेकिन विमानन, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और रिटेल जैसे ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में वेतन में कटौती और छंटनी की आशंका है। देश में बंदी के कारण इन क्षेत्रों की मांग में भारी गिरावट आई है। अगर मौजूदा वैश्विक और आर्थिक सुस्ती जारी रहती है तो इससे मांग और कीमत पर प्रभाव पड़ेगा। इस्पात, रत्न एवं आभूषण, निर्माण और इंजीनियरिंग और कपड़ा क्षेत्रों के भी इससे प्रभावित होने की आशंका है।

(साथ में देव मुखर्जी, सोहिनी दास, विवेट पिंटो और अभिषेक रक्षित)

फर्मों को राहत देने के लिए बैंक मांग रहे आरबीआई से मंजूरी

देव चटर्जी और अभिजित लेले
मुंबई, 20 मार्च

विश्वव्यापी कोरोनावायरस महामारी के कारण कंपनी जगत नकदी प्रवाह पर असर महसूस कर रहा है, ऐसे में भारतीय बैंक उधार लेने वालों को राहत की पेशकश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी मांग रहे हैं। साथ ही बैंक चाह रहे हैं कि मार्च तिमाही में प्रभावित क्षेत्रों को फंसे कर्ज के तौर वर्गीकृत न किया जाए।

भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि बैंक विमानन, पर्यटन, छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों जैसे क्षेत्रों का आकलन कर रहा है, जिस पर कोरोनावायरस महामारी का नकारात्मक असर पड़ा है। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था पर भी इसका कुछ असर होगा। एक सूत्र के मुताबिक, बैंक छोटे व मझोले आकार वाली कंपनियों को आसान उधारी की पेशकश करने के लिए तैयार है, जिसने मौजूदा तिमाही में ज्यादा दबाव का सामना किया है क्योंकि आपूर्ति शृंखला में अवरोध और ग्राहकों के अभाव से उनकी बिक्री प्रभावित हुई है।

छोटे व मझोले उद्योगों को आसान उधारी और कर्ज के पुनर्भुगतान पर मोहलत देना चाहते हैं बैंक

एक बैंकर ने कहा, कर्ज पुनर्भुगतान में देरी के लिए कंपनियां मोहलत चाह रही हैं और हमने इसके लिए आरबीआई की मंजूरी मांगी है। चूंकि यह अप्रत्याशित घटना है, लिहाजा हमें लगता है कि कंपनियों को राहत देने का मामला बनता है।

बोफा सिक्योरिटीज का अनुमान है कि एक महीने की बंदी से भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर सालाना 50 आधार अंक का असर होगा। रेटिंग फर्म मूडीज ने भी भारत व विदेश में बंदी से कंपनी के नकदी प्रवाह पर असर को लेकर चेताया है और कई कंपनियां कर्ज भुगतान में चूक करेंगी।

बैंकर इसे लेकर भी चिंतित हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों को उधारी की रफ्तार घटकर 1.6 फीसदी रह गई है क्योंकि मध्यम व बड़े उद्योगों में क्रमश: 2.5 फीसदी व 1.8 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई है। इसके अलावा कुल औद्योगिक उधारी में करीब 70 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाले बड़े क्षेत्रों की उधारी की रफ्तार नकारात्मक से लेकर निचले स्तर पर रही है, जिनमें बुनियादी ढांचा, पेट्रोलियम, रसायन, धातु और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी तिमाही में इन औद्योगिक क्षेत्रों की हिस्सेदारी फंसे कर्ज में सबसे ज्यादा रही है, जो उधारी की रफ्तार पर और असर डाल रहा है। कंपनियों के वित्तीय प्रमुख ने कहा है कि महामारी से मार्च तिमाही में भी अवरोध पैदा हो सकता है। बजाज ग्रुप के समूह निदेशक (वित्त) पी. बनर्जी ने कहा, यह परिदृश्य काफी खराब है। कंपनियों को दो साल के लिए मूलधन के पुनर्भुगतान पर मोहलत मिलनी चाहिए और ब्याज भुगतान पर छह महीने की। ब्याज दरों को समायोजित कर कर्ज की मौजूदा शुद्ध वैल्यू को भी संरक्षित किया जाना चाहिए।

विमानन, हवाईअड्डे, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और रिटेलरों समेत उच्च जोखिम वाले सेवा क्षेत्रों को मोहलत मिलनी चाहिए। क्रिसिल ने गुरुवार के नोट में चेतावनी देते हुए कहा है, कुछ प्रभावित कंपनियां लागत कटौती के कदम उठा सकती हैं, लेकिन यह शायद पर्याप्त नहीं होगा। स्टील, रत्न व आभूषण, निर्माण व इंजीनियरिंग और वस्त्र जैसे क्षेत्रों पर कोरोनावायरस महामारी का शायद सीधा असर नहीं होगा, लेकिन मौजूदा वैश्विक व देसी आर्थिक मंदी का मांग और बिक्री से मिलने वाली कीमत पर असर होगा।

राहत की उम्मीद से बाजार को करार

पृष्ठ-1 का शेष

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में रिटेल शोध प्रमुख दीपक जसानी ने कहा, 'बाजार में लगातार 30 फीसदी की गिरावट के बाद यह तेजी आई है। आमतौर पर इतनी बड़ी गिरावट के बाद बाजार में कुछ दिनों तक तेजी बनी रहती है। हालांकि बिकवाली के फिर से हावी होने की आशंका बनी हुई है।' जसानी ने कहा, 'पिछली दो तिमाहियों से कंपनियों की कमाई प्रभावित हुई है और वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ रहा है। ऐसे में उच्चतर स्तर पर निवेशक मूल्यांकन पर पुनर्विचार कर सकते हैं और इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी कम घटा सकते हैं।'

जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, 'एशियाई और यूरोपीय बाजारों में बढ़त की वजह से घरेलू बाजार में तेजी आई है और परिदृश्य में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आया है।' शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव को मापने का सूचकांक इंडिया वीआईएक्स 7 फीसदी कम होकर 67 के स्तर पर रहा, जोकि अब भी ऊंचा बना हुआ है।

तेजी के बावजूद 587 शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर को छुआ और 351 में लोअर सर्किट लगाना पड़ा। सेंसेक्स में दो शेयरों को छोड़कर सभी बढ़त पर बंद हुए। तेल की कीमतों में सुधार से ओएनजीसी में सबसे ज्यादा 18 फीसदी की तेजी आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज 11 फीसदी बढ़त पर बंद हुआ। हालांकि एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक में गिरावट दर्ज की गई। बीएसई के सभी क्षेत्रवार सूचकांक लाभ में रहे। ऊर्जा और तेल एवं गैस सूचकांक में सबसे ज्यादा तेजी आई।

कच्चा तेल चढ़ा, सोने और चांदी में भी आई तेजी

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 20 मार्च

चीन में फैक्टरियों और रिटेल शोरूमों को कई सप्ताहों के बाद पुन: खोले जाने की खबरों से कच्चे तेल, कीमती धातुओं और अन्य धातुओं में शुक्रवार को कुछ सुधार देखने को मिला। कोरोनावायरस के प्रसार की वजह से चीन में कई सप्ताह तक फैक्टरियों और शोरूमों को बंद कर दिया गया था।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अप्रैल 2020 का सोना वायदा 2 प्रतिशत तक चढ़कर शुक्रवार को 40,624 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। कारोबारियों ने कीमतों में और ज्यादा वृद्धि की आशंका के बीच अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खरीदारी पर जोर दिया। चांदी मई अनुबंध वायदा 2020 एमसीएक्स पर दिन के कारोबार के अंत में 2.87 प्रतिशत मजबूत होकर 36,109 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचा।

कच्चा तेल वायदा 4.39 प्रतिशत तक चढ़कर 2,067 रुपये प्रति बैरल पर पहुंचा। कच्चे तेल वायदा में इस उम्मीद से तेजी आई कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक) अपने सदस्यों की आपात बैठक आयोजित करेगा और कीमत में गिरावट दूर करने के लिए अपने उत्पादन में कटौती पर सहमति बनाएगा। एमसीएक्स पर कच्चा तेल वायदा 8 प्रतिशत तक चढ़ गया था, जो बाद में थोड़ा कमजोर हो गया। रूस द्वारा कच्चा तेल उत्पादन में कटौती से इनकार किए जाने से ओपेक और रूस के बीच कीमत युद्ध बढ़ा है जिससे ऊर्जा कीमतों में चीन में कोविड-19 के प्रसार के बाद से 50 प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट आई है।

केडिया कमोडिटी के निदेशक अजय केडिया ने कहा, 'चीन के वुहान क्षेत्र में कोविड-19 का कोई नया मामला सामने नहीं आने से शुक्रवार को धारणा सकारात्मक दिखी। वुहान इस मौजूदा महामारी का केंद्र है जहां से पूरी दुनिया में इस वायरस का प्रसार हुआ है। कई सप्ताह की बंदी के बाद वहां फैक्टरियां और रिटेल शोरूम खुलने शुरू हो गए हैं। जहां कई एशियाई और यूरोपीय देशों में कोविड-19 का खतरा बना हुआ है और कामकाज बंद रखने का सिलसिला जारी है, वहीं चीन में व्यापार के आंशिक रूप से बहाल होने से उम्मीद की किरण लौट रही है। आगामी सप्ताहों में मांग में सुधार आने की उम्मीद दिख रही है।'

- चीन में बंद शोरूमों और फैक्टरियों के खुलने से धारणा में आ रहा है बदलाव
- एमसीएक्स पर अप्रैल 2020 का सोना वायदा 2 प्रतिशत तक चढ़कर 40,624 रुपये पर पहुंचा

इस बीच, शांघाई कमोडिटी एक्सचेंज की तज़ पर लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) पर भी बेस मेटल में तेजी आई है। इसी तरह का रुझान तांबा वायदा में देखने को मिला। एमसीएक्स पर अप्रैल डिलिवरी का तांबा वायदा शुक्रवार को 1 प्रतिशत तक चढ़कर 378.3 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। एलएमई पर तेजी के बाद शुक्रवार को जस्ता और सीसा वायदा में 1.5 और 2.5 प्रतिशत के बीच तेजी आई।

डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट की वजह से अंतरराष्ट्रीय कीमतों की तुलना में भारतीय एक्सचेंजों पर धातु और ऊर्जा की कीमतों में ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। भारतीय रुपया शुक्रवार को फिसलकर डॉलर के मुकाबले 75 से नीचे कारोबार कर रहा था।

शुक्रवार को हाजिर बाजार में, सोने का भाव लगभग 2 प्रतिशत तक चढ़कर 41,169 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी 5 प्रतिशत की तेजी के साथ 37,140 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही, जबकि गुरुवार को यह 35,220 रुपये पर थी। सराफा कीमतों में सुधार से कारोबारियों और उपभोक्ताओं को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूदा अनिश्चितता के बीच नए ऑर्डरों से दूर रहने को बाध्य किया।

अर्थव्यवस्था के लिए मौद्रिक राहत के प्रयास में पूंजी लगाने के यूरोपीय संघ के निर्णय के बीच जिंस व्यापार में भी धारणा मजबूत हुई। हालांकि जहां चीन ने कोविड-19 महामारी के प्रसार पर लगभग नियंत्रण पा लिया है, लेकिन यूरोपीय संघ और अन्य विकसित तथा विकासशील देश इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं।

राणा कपूर 2 अप्रैल तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में

सुब्रत पांडा
मुंबई, 20 मार्च

संकट से जूझ रहे येस बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी राणा कपूर को मुंबई सत्र न्यायालय ने 2 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके पहले जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज न्यायालय से कहा कि उन्हें अब कपूर को और ज्यादा हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।

वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राणा कपूर को हिरासत में लेने के लिए पेशी वारंट जारी किया है। सीबीआई राणा कपूर के खिलाफ कथित रूप से नई दिल्ली में गौतम थापर के अवंता ग्रुप से नई दिल्ली में संपत्ति के रूप में अवैध तरीके से पारितोषिक पाने के मामले की जांच कर रही है, जिसके बदले में औद्योगिक परिवार का बकाया माफ किया गया और नए कर्ज दिए गए।

इसके पहले कपूर की ईडी की हिरासत 4 दिन के लिए 20 मार्च तक बढ़ा दी गई थी, उस समय 6 दिन की हिरासत की मांग की गई थी। पूर्व बैंकर को धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत ईडी ने 8 मार्च को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ही वह ईडी की हिरासत में हैं। पूर्व में दी गई हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद ईडी ने कपूर को अदालत के समक्ष पेश किया।

62 साल के कपूर ने आज न्यायालय से कहा कि वह अस्थमा से पीड़ित हैं और उम्र ज्यादा होने की वजह से वह कोरोनावायरस के शिकार हो सकते हैं। न्यायालय ने जेल अधिकारियों के कहा कि वह इसे ध्यान में रखते हुए पूरी सावधानी बरतें।

जांच एजेंसी ने अनिल अंबानी, नरेश गोयल, कपिल और धीरज वधावन, सुभाष चंद्रा और समीर गहलोत सहित उद्योग जगत के दिग्गजों को येस बैंक मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है।

जांच के घेरे में कई उद्यमी

- न्यायालय से प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अब उसे कपूर को हिरासत में रखने की जरूरत नहीं
- न्यायालय ने कपूर को 2 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा
- उन्हें 30 मार्च को फिर से न्यायालय के सामने पेश होना है
- कपूर के अलावा अनिल अंबानी सहित कई उद्यमियों से हो रही पूछताछ

पूर्व बैंकर राणा कपूर को को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत ईडी ने 8 मार्च को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से ही वह ईडी की हिरासत में थे

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि अनिल अंबानी से ईडी ने गुरुवार को पूछताछ की थी और कुछ महत्त्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जो इस मामले में अहम हैं। एडीएजी बैंक के बड़े कर्जदारों में से है, जिसका बकाया करीब 13,000 करोड़ रुपये है। अंबानी ने एजेंसी से और समय मांगा है, जिससे वह मांगी गई कुछ विशेष जानकारियों पर स्पष्टीकरण दे सकें। जांच एजेंसी ने उन्हें 30 मार्च को फिर पेश होने को कहा है।

येस बैंक के अन्य बड़े चूककर्ताओं को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जो अभी पेश नहीं हुए हैं।

जांच के दौरान एजेंसी ने पाया कि मैक स्टार मार्केटिंग को 202 करोड़ रुपये कर्ज दिया गया, जो एचडीआईएल के प्रवर्तकों सारंग वधावन, राकेश वधानव और पंजाब ऐंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन वरयाम सिंह और डी शॉ ग्रुप का संयुक्त उद्यम है। पहले तीन की इस उद्यम में हिस्सेदारी महज 16.64 प्रतिसत है, जबकि डी शॉ ग्रुप की बहुलांश हिस्सेदारी है।

ईडी ने पाया कि मैक स्टार मार्केटिंग को दिए गए 202 करोड़ रुपये कर्ज का इस्तेमाल एचडीआईएल ने पहले के कर्ज को चुकाने के लिए किया। बहरहाल इस उद्यम को कार्यालय के भवन की मरम्मत के लिए यह कर्ज दिया गया था।

आगे और जांच से पता चला है कि करीब 78 कंपनियां कपूर परिवार के सदस्यों की हैं, जिनका नियंत्रण व प्रबंधन कपूर करते थे।

ईडी ने यह भी पाया कि येस बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनैंस में 3,700 करोड़ रुपये का डिबेंचर लिया था, जबकि दीवान हाउसिंग ने कपूर की बेटियों के मालिकाना वाली कंपनियों को 600 करोड़ रुपये कर्ज दिया था। दोनों लेन देन संदेहास्पद थे क्योंकि कपूर की बेटियों के नाम वाली कंपनियों का पर्याप्त कारोबार या संपत्ति नहीं है। साथ ही कर्ज के लिए दिखाई गई गिरवी सिर्फ एक संपत्ति थी, जिसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपये है। गिरवीं रखी गई संपत्ति कृषि भूमि है, जिसे आवासीय जमीन के रूप में उसका दाम बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया।

येस बैंक के बोर्ड में आर गांधी और अनंत गोपालकृष्णन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को आर गांधी और अनंत नारायण गोपालकृष्णन को निजी क्षेत्र के येस बैंक के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 26 मार्च 2020 से दो साल के लिए की गई है।

येस बैंक के बोर्ड में आर गांधी का यह दूसरा कार्यकाल होगा। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर गांधी इसके पहले मई 2019 में रिजर्व बैंक द्वारा अतिरिक्त निदेशक के रूप में 2 साल के लिए नियुक्त किए गए थे। उनका कार्यकाल मई 2021 तक था, लेकिन इस महीने की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने येस बैंक के पहले के बोर्ड को भंग कर दिया था।

अनंत नारायण गोपालकृष्णन एसपी जैन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट ऐंड रिसर्च में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और इंटरनैशनल बैंकिंग और वित्तीय बाजारों के विशेषज्ञ हैं। *बीएस*

जल्द आ सकती है बल्क दवा नीति

सोहिनी दास
मुंबई, 20 मार्च

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश में बल्क दवाओं के विनिर्माण और वृद्धि को बढ़ाने की नीति को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सरकार इस तरह का माहौल बनाने की कवायद कर रही है, जिससे स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिले और दवा बनाने के लिए चीन से कच्चे माल के आयात पर निर्भरता कम की जा सके।

मेडिकल उपकरणों को लेकर भी एक नीति तैयार की जा रही है।

सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में सप्ताह के अंत तक घोषणा किए जाने की उम्मीद है। इस नीति का स्पष्ट ब्योरा अभी आना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि यह नीति बड़े पैमाने पर देश में विनिर्माण को बल देने वाली होगी। उद्योग के एक सूत्र ने कहा, 'इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने का विचार है। औषधि विभाग (डीओपी) लंबे समय से इस पर काम कर रहा है और इसके बारे में हाल में प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष भी प्रस्तुति हुई थी।'

उन्होंने कहा कि सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग भी नीति तैयार करने में नजदीकी से लगा हुआ है। सरकार 3,000 से 5,000 करोड़ रुपये का फंड बनाने की योजना बना रही है, जिसे देश में बल्क दवाओं के विनिर्माण के लिए आधार तैयार किया जा सके। यह धन बल्क दवाओं के आयात पर उपकर लगाकर और केंद्र की ओर से कुछ वित्तपोषण के माध्यम से जुटाया जा सकता है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत सस्ती बिजली, पानी, शोधन संयंत्र, तकनीकी नवोन्मेश जैसी मदद मुहैया कराई जा सकती है। उन्होंने कहा, 'यह प्रोत्साहन बड़ी इकाइयों को दिया जा सकता है। अगर कोई 500 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा का निवेश करना चाहता है तो वह इसका पात्र होगा। इसका आकार सस्ता मूल्य सुनिश्चित करने के लिए तय किया जा रहा है।'

इसके पीछे विचार है कि भारत में कुछ बड़े क्लस्टर तैयार किए जाएं, जहां बड़ी इकाइयां हों। इनका विकास विशेष उद्देश्य इकाइयों के माध्यम से किा जा सकता है और जो यहां जगह लेंगे, उनके लिए प्लग ऐंड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर की पेशकश की जा सकती है। एसपीवी जरूरी पर्यावरण मंजूरी दिलाने में भी मदद करेगी, जो बल्क दवा उद्योग के विकास में बड़ी बाधा है।

सरकार ने 38-40 बल्क ड्रग को चिह्नित किया है, जिन पर भारत बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर है। इन दवाओं का विनिर्माण करने वाली इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मेडिकल उपकरण नीति लाने की भी चल रही है तैयारी

- बल्क दवा के मामले में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत में विनिर्माण का माहौल बनाने की कवायद
- बल्क दवाओं के आयात पर उपकर लगाकर और केंद्र से पैसे लेकर 3,000 से 5,000 करोड़ रुपये का कोष बनाया जा सकता है
- चीन से आने वाली 38-40 बल्क ड्रग चिह्नित, इनके विनिर्माण को मिलेगी प्राथमिकता

चीन के वुहान से बल्क दवाओं की आपूर्ति बहाली की ओर

सोहिनी दास
मुंबई, 20 मार्च

चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से भारत को होने वाली बल्क दवाओं की आपूर्ति पर लगी रोक हालात में थोड़े सुधार के साथ ही बहाल होने लगी है। कोरोना के प्रसार के केंद्र में रहे वुहान के दवा आपूर्तिकर्ताओं ने भी अपने भारतीय खरीदारों के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू कर दी है।

एक बड़ी दवा कंपनी के चेयरमैन ने बिज़नेस स्टैंडर्ड के साथ बातचीत में कहा कि चीन से दवाओं की बल्क आपूर्ति बहाल होने लगी है। उन्होंने कहा, 'यहां तक कि कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित रहे वुहान के आपूर्तिकर्ताओं ने भी हमसे संपर्क साधना शुरू कर दिया है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है।' उन्होंने कहा कि बंदरगाहों पर दबाव अधिक होने से यह माल मुख्यत: हवाई मार्ग से लाया जाएगा।

चीन में वायरस से संक्रमित होने वाले नए लोगों की संख्या में कमी आ रही है जिससे वहां पर विनिर्माण उद्योग धीरे-धीरे पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा है।चीन ने कहा था कि बुधवार को हुबेई प्रांत और उसकी राजधानी वुहान में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। हुबेई के करीब 40 आपूर्तिकर्ता भारत को थोक दवाओं, मध्यवर्ती सामग्रियां या प्रमुख बुनियादी औषधि सामग्रियों को निर्यात करते रहे हैं।

जेबी केमिकल्स के अध्यक्ष प्रणब मोदी ने कहा, 'वुहान के आपूर्तिकर्ता भारत की कंपनियों के साथ बात कर रहे हैं। प्रतिबंधित निर्यात उत्पादों की सूची में रखे गए कुछ उत्पादों की आपूर्ति भी जल्द ही शुरू होने की संभावना है।' कोरोना संकट के चलते चीन के बंदरगाहों पर अटके माल की भी आवाजाही शुरू हो गई है। उम्मीद है कि यह माल इस महीने के अंत तक भारत पहुंच जाएगा।

मोदी का मानना है कि वुहान के दवा विनिर्माताओं को दो महीने की बंदी के बाद पूरी क्षमता से उत्पादन के स्तर तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि एक महीने बाद हालात काफी हद तक सामान्य हो जाएंगे।

भारत सक्रिय औषधीय सामग्रियों (एपीआई) एवं थोक दवाओं के लिए चीन पर बुरी तरह आश्रित रहा है। भारत में दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की करीब 70 फीसदी आपूर्ति चीन ही करता है। इस कच्चे माल से भारत में बड़े पैमाने पर एंटीबायोटिक एवं विटामिन दवाएं बनाई जाती हैं। चीन से आपूर्ति बाधित होने पर भारतीय औषधि बाजार में काफी आपाधापी हो गई थी।

भारतीय औषधि निर्माताओं ने अपने पास दो-तीन का बफर स्टॉक जमा होने का दावा किया वहीं सरकार ने जरूरी दवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए 13 प्रमुख एपीआई के निर्यात को निषिद्ध कर दिया।

वैश्विक महामारी
कोरोनावायरस

- वायरस से संक्रमित होने वाले नए लोगों की संख्या में कमी आ रही है जिससे वहां पर विनिर्माण उद्योग धीरे-धीरे खड़े होने की कोशिश कर रहा है
- नए संक्रमण मामलों में कमी आने के बीच चीन के आपूर्तिकर्ताओं ने भारतीय दवा कंपनियों के साथ बातचीत की शुरू
- बंदरगाहों पर दबाव अधिक होने से यह माल मुख्यतः हवाई मार्ग से लाया जाएगा

सैनिटाइजर उत्पादन में सरकार दिखी सक्रिय

वीरेंद्र सिंह रावत और
सोहिनी दास
लखनऊ/मुंबई, 20 मार्च

कोरोनावायरस के प्रसार के कारण उपजे डरावने माहौल में सैनिटाइजर की बिक्री में आई उछाल को देखते हुए सरकार उपभोक्ताओं तक इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हो गई है। इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें राज्यों को इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कहने, कच्चे माल की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने और निर्यातों पर प्रतिबंध लगाने जैसे निर्णय शामिल हैं।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को 19 मार्च को पत्र लिखकर सैनिटाइजर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने लिए कहा है। इसमें सैनिटाइजर निर्माण वाली इकाइयों को बिना किसी सीमा के एथनॉल के भंडारण के लिए जरूरी अनुमति देना शामिल है। बहरहाल, सैनिटाइजर उद्योग को तीन पालियों में परिचालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। डिस्टिलरी उद्योग को भी थोक में सैनिटाइजर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसे बाद में सैनिटाइजर इकाइयां पैक कर बाजार में उतार सकती हैं।

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में भरोसा दिया है कि घरेलू चीनी उद्योग जरूरत के मुताबिक एथनॉल या ईएनए की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करेगा ताकि हैंड सैनिटाइजर की बढ़ी मांग को पूरा किया जा सके। बुधवार को लिखे अपने पत्र में इस्मा ने सैनिटाइजर विनिर्माताओं को सुझाव दिया है कि वे एथनॉल या ईएनए की जरूरत की पूर्ति के लिए सीधे चीनी मिलों से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ (यूपीएसएमए) के सचिव दीपक गुप्ता ने कहा कि राज्य में फिलहाल करीब 50 चीनी मिलें एथनॉल/ईएनए का उत्पादन कर रहे हैं। चीनी उद्योग कोरोनावायरस के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में सक्रियता से योगदान देना चाहता है। भले ही देश में ज्यादातर हैंड सैनिटाइजर आईसोप्रोपाइल एल्कोहल (आईपीए) से बानए जा रहे हैं लेकिन इसे इथाइल एल्कोहल/ एथनॉल से भी बनाया जा सकता है। चूंकि बढ़ी हुई मांग और घबराहट में खरीदारी किए जाने से बाजार में हैंड सैनिटाइजर की भारी कमी हो गई है, यूपी में विनिर्माता पहले से स्थानीय डिस्टिलरियों से इथाइल एल्कोहल की खरीद की गुंजाइश तलाश रहे थे।

कर्मचारियों की मदद को लेकर उद्योगों का समर्थन

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 20 मार्च

उद्योगों द्वारा कर्मचारियों के वेतन काटने और छटनी से बचने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के एक दिन बाद उद्योग संगठनों ने इस अपील की सराहना की, लेकिन उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है।

गुरुवार को 30 मिनट के भाषण में मोदी ने कारोबारी समुदाय के साथ-साथ कंपनियों से अपने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने और यात्रा तथा अन्य पाबंदियों के कारण उनके काम पर नहीं आ सकने पर उन्हें दंडित नहीं करने को कहा था। प्रधानमंत्री ने कंपनियों को इस समय कर्मचारियों के साथ पूरी मानवीयता के साथ काम लेने और उनका वेतन न काटने की अपील की थी।

सभी उद्योग संगठनों ने प्रधानमंत्री का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाजार में मांग कम है और कोरोना संकट की वजह से स्थिति और खराब होने की संभावना है।

सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने कहा- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) अपने सदस्यों से कह रहा है कि वे प्रधानमंत्री की सलाह के मुताबिक कार्यस्थल पर ठेके के कर्मचारियों सहित सभी कर्मियों की सहायता करें। उद्योग संगठन में 9,100 सदस्य हैं, जिसमें सार्जनिक के साथ सरकारी क्षेत्र भी शामिल है। इसकी अप्रत्यक्ष सदस्यता 3,00,000 से ऊपर है, जो 291 राष्ट्रीय व क्षेत्रवार संगठनों से जुड़े हैं। किर्लोस्कर ने कहा कि हम सक्रियता के साथ सरकार को निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के इस्तेमाल की पेशकश कर रहे हैं और कर्मचारियों व सेवा प्रदाताओं की सुरक्षा का ध्यान दे रहे हैं, साथ ही इस कठिन घड़ी में उनकी जीविका का भी संरक्षण कर रहे हैं।

- फिक्की और सीआईआई ने अपने सदस्यों को प्रधानमंत्री का संदेश भेजा और पूर्ण मदद का आश्वासन दिया
- हालांकि उद्योगों का कहना है कि यह मदद उद्योगों की स्थिति पर निर्भर होगी
- पहले से बेहाल छोटे उद्यमों ने स्थिति को लेकर जताई निराशा
- कहा कि रोजाना मजदूरी पर काम करने वाले मजदूरों के लिए योजना बनाए सरकार

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है। फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा- प्रधानमंत्री को सबसे पहले सार्वजनिक स्थिति, इलाज से जुड़े पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर तबके को लेकर उचित अपील की क्योंकि उनकी मजदूरी बंद होती है तो यह उनके लिए खतरनाक होगा।

दोनों उद्योग संगठनों ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का संदेश पंजीकृत सदस्यों को भेज दिया है, लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति ही भविष्य तय करेगी।

वहीं छोटे उद्योगों से जुड़े संगठनों को अनिश्चितता की घड़ी में कम उम्मीद नजर आ रही है। फेडरेशन आफ इंडियन एमएसएमई (फिस्मे) के महासचिव अनिल भारद्वाज ने कहा, 'चमड़ा, परिधान और रत्न एवं आभूषम जैसे कुछ क्षेत्र पहले से ही कम मांग के संकट से जूझ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका से मांग घट रही है और ऑर्डर रद्द हो रहे हैं। निर्यातकों का कारोबार खराब हो रहा है, ऐसे में प्राथमिक उत्पादकों को भी नुकसान हो रहा है।' कन्फेडरेशन आफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के सूत्रों ने भी कहा कि कोरोनावायरस के संकट के बाद अनौपचारिक क्षेत्र में का करने वाले लोगों को आर्थिक नुकसान से बचाने का कोई रास्ता नहीं है। कैट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अगर दुकान बंद हो जाती है तो हाथ से गाड़ी खींचने वालों के नुकसान से कैसे बचा जा सकता है? उनका ध्यान कौन रखेगा? हम उम्मीद करते हैं कि आर्थिक कार्यबल इस दिशा में कुछ कदम उठाएगा।'

वसूली रोकने का आदेश बरकरार

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 20 मार्च

सर्वोच्च न्यायालय ने आज वसूली प्रक्रिया को 6 अप्रैल तक टालने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने कोरोनावायरस के प्रसार की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कर विभागों और वित्त संस्थाओं को वसूली प्रक्रिया को उक्त अवधि तक टालने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अगुआई वाले पीठ ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों पर गौर किया जिसमें कहा गया था कि केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाए जाने की जरूरत है।

मेहता ने पीठ को बताया कि इसी तरह का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी दिया था।

मामले को स्पष्ट करते हुए केपीएमजी में कर पार्टनर हरप्रीत सिंह ने कहा, 'केरल उच्च न्यायालय ने कोरोनावायरस के प्रसार से उपजे डरावने माहौल का स्वत: संज्ञान लेते हुए कर अधिकारियों, वस्तु एवं सेवा कर और मूल्य वर्धित कर वसूलने में लगे अधिकारियों, वित्त संस्थाओं, बैंकों आदि को निर्देश दिया था कि वसूली प्रक्रिया या दंडात्मक कार्रवाई को 6 अप्रैल तक टाल दिया जाए।'

केरल उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने इस बात का संज्ञान लिया था कि सरकारी विभाग वसूली नोटिस भेज रहे हैं जिससे वादियों को अंतरिम आदेश लेने के लिए अदालत आने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

केरल उच्च न्यायालय ने कहा, 'उच्च न्यायालय के कर्मचारी और महाधिवक्ता के स्टाफ बिना किसी सावधानी को अपनाए हाथों से ही दस्तावेजों का रखरखाव करते हैं। वे दस्तानों का उपयोग किए बिना ही खुले हाथों से इस काम को करते हैं।...'

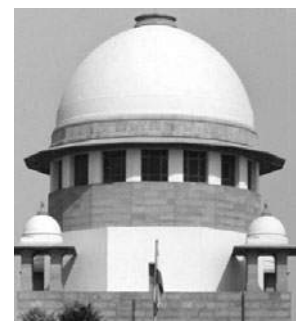

- सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के वसूली रोकने के आदेश को रखा बरकरार
- अदालत के फैसले के खिलाफ केंद्र ने लगाई थी याचिका

बीएस सूडोकू 3694 | परिणाम संख्या 3693

4	5				2		6	
9	6						2	7
1			9	3				4
		4	2	1			7	5
			6		3			
2	9			7	5	1		
3				6	7			2
5	7						1	6
	4		5				3	9

5	7	6	4	2	9	3	8	1
2	8	4	5	1	3	9	6	7
9	1	3	7	8	6	2	5	4
3	4	8	6	9	5	1	7	2
1	5	2	8	3	7	4	9	6
7	6	9	2	4	1	5	3	8
8	9	5	1	6	2	7	4	3
4	3	1	9	7	8	6	2	5
6	2	7	3	5	4	8	1	9

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2030/2040, जौ 1825/1850, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2200, सरसों 3450/3550, तिल सफेद 8600/8800, सोया (टीन) 1440/1450, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1350/1400,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2040/2050, गेहूं शरबती 2825/2925, चावल शरबती सेला 3400/3450, स्टीम 3750/3800, लालमती 2900/2950, चावल (सोना) 2600/2650,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1330, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1415, फ्लैक 1345, डीएमओ 970, टरपीन लैस बोल्ड 1430

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1025/1080, खुरपा 960/985,चाकू 1030/1090, रसकट 900/945, शक्कर 1100/1125, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 3250, सिहोरा 3120, बुंदकी 3130, बुढ़ाना 3180,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3450/3500, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1000/1025, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 3950, खल: सरसों 2100/2200, बिनौला 2150/2250, चना छिलका 2100/2150,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 4700/4800, गेहूं (मिल) 2090/2100, मक्की 1700/1750, बाजरा 1550/1600, जौ 1775/1800, ग्वार लूज 3200/3250, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4040/4050,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 1900/2000, ग्वार 3200/3250, जौ 1850/1900,

जोधपुर
गेहूं 2050/2100, जौ 1800/1825, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 3400/3450, ग्वारगम 5300/5350, बाजरा (गुजरात) 1600/1650, बाजरा (जयपुर) 1600/1650, चना 4000/4150,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)94, राइसब्रान (अखाद्य) 91, खल सरसों 1950, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 850, लाल 850, कंटीन्यूअस 900,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 9000/9200, अरहर दाल 7400/8000, उड़द साबुत 7300/8200, उड़द धोया 8800/9400, छिलका 8300/8700, दाल मसूर 6200/6500, चनादाल 5100/5200,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 5400/5500, सेला 4900/5000, शरबती साधारण सेला 3400/3500, शरबती स्टीम 3900/4000,चावल 1509 सेला 4450/4500, धान: शरबती 1950/2000, बासमती 1121 धान 2700/2800,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 3840/3890, हरियाणा 3840/3850, राजस्थान 3780/3820, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2250/2350, सरसों खल 1990/2000,

फाजिल्का
(जीएसटी अतिरिक्त): धान (1509) 2400/2450, धान मोटा 1550/1575, चावल कच्चा (आईआर-8)2200/2300, चावल सेला (आईआर-8) 2200/2250, चावल कच्चा (पीआर-11) 2700/2800,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2060/2080, चावल परमल कच्चा 2300/2325, से ला 2225/2260, मक्की यूपी 1750/1775, दाल उड़द छिलका 8800/10000, चना देशी 4950/5050, दाल चना 5200/5300, काबली चना 5100/6300, राजमां चित्रा पुणे 7800/8800, चीन 8700/8800,

करनाल
गेहूं दड़ा 2050/2060, बासमती चावल 5500/5550, धान 1121 नं. 2650/2725, पूसा 1509 धान 2300/2400, शरबती धान 1900/1925, सेला (1509 नं.) चावल 4250/4350, स्टीम 5400/5500,

हिसार
ग्वार 3200/3250, जौ 1840/1850, सरसों 3550/3700, मूंग 7000/7100, गेहूं 2040/2050,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2130, आटा (प्रति 44 किलो) 975/1000, मैदा 1100/1120, देशी घी (एक ली/जार) 308/470, रिफाइंड (टीन) 1310/1340,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 3750/3800, खल बिनौला मोटी 2100/2300, बिनौला 2500/3100, सरसों तेल 8250/8300, गेहूं 2000/2100, ग्वार 3250/3300, बाजरा 1575/1600 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 29

सामाजिक गोलबंदी

कोविड-19 के 10,000 से अधिक मामलों वाले सात में से चार देश- इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इस विषाणु के उद्गम चीन के अलावा इस सूची में एशिया का महज एक और देश ईरान है। दस हजार से अधिक संक्रमण वाला सातवां देश अमेरिका है। 1,000 से लेकर 10,000 मामलों तक वाले नौ देशों में से एक को छोड़कर बाकी सभी देश यूरोप में ही हैं। इस सूची में अकेला एशियाई देश दक्षिण कोरिया है। बड़ी आबादी वाले अन्य एशियाई देशों- भारत, इंडोनेशिया और जापान में अभी तक अपेक्षाकृत कम मामले आए हैं और भारत करीब 200 मामलों के साथ इनमें सबसे कम प्रभावित है।

अगर भारत यूरोप की राह पर चला होता तो बड़ी आबादी के अनुपात में यहां पर पीड़ितों की संख्या करीब दो लाख होती और तब इस पर काबू कर पाना मुमकिन नहीं होता। भारत से थोड़ी कम आबादी वाले अफ्रीकी महाद्वीप में कोविड-19 संक्रमण की संख्या भारत से चार-पांच गुनी पहुंच चुकी है। भारत की आधी आबादी वाले लैटिन अमेरिका में भारत की तुलना में करीब दस गुना मरीज हैं।

विषाणु संक्रमण के पुराने मामलों में अधिकांश प्रभावित लोग उसी देश या महाद्वीप के थे जहां इसकी शुरुआत हुई थी। वर्ष 2014 में इबोला वायरस की शुरुआत पश्चिमी अफ्रीका से हुई थी और उसने वहीं के लोगों को चपेट में लिया था। वर्ष 2003 में सार्स के 8,000 संक्रमित लोगों में से करीब 90 फीसदी चीन एवं हॉन्गकॉन्ग के ही थे। जानलेवा वायरस एचआईवी-एड्स की चपेट में आने वाले सबसे ज्यादा लोग इसके उद्गम अफ्रीका के ही रहे हैं।

पूर्वी एशियाई देशों में सघन विमानन नेटवर्क होने से यह इलाका अपने सीमित चिकित्सा संसाधनों, अधिक भीड़ वाली रिहाइश और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खराब मानकों की वजह से अधिक असुरक्षित माना जाएगा। ये कारक अब भी प्रभावी हो सकते हैं। दक्षिण कोरिया ने व्यापक स्तर पर परीक्षण का तरीका अख्तियार किया है। इस वजह से कोरिया में संक्रमण के अधिक मामले दर्ज हुए लेकिन जल्द पता लगने से उन पर काबू पाने में आसानी हुई है। भारत और जापान ने अमेरिका की ही तरह अपने नागरिकों का कोरोना संक्रमण परीक्षण काफी कम किया है। ऐसी आशंका है कि परीक्षण में तेजी आते ही यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। भारत के संक्रमण आंकड़े भी काफी हद तक वैसा ही रुझान दिखाने लगे हैं जैसा बाकी प्रभावित देशों में दर्ज किया गया है।

ऐसे हालात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में अपनी सरकार का संकल्प जताया है। उन्होंने कहा है कि भारत इस महामारी को हल्के में नहीं लेगा और सरकारी प्रयासों से अलग स्तर तक जाकर इसका मुकाबला करेगा। खुद नागरिकों को ही अपनी भलाई के लिए जिम्मेदार बनाने की कोशिश की जाएगी। जोर रोकथाम पर है क्योंकि महामारी के स्तर वाली बीमारी का प्रसार होने के बाद उस पर काबू पाने की कोई भी कोशिश नाकाफी चिकित्सा सुविधाओं से प्रभावित होगी। अगर यह तरीका कारगर होता है तो यह सामाजिक गोलबंदी में नरेंद्र मोदी का दूसरा सफल प्रयोग होगा।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

मोदी ने इस तरह का पहला अभियान अच्छी आर्थिक स्थिति वाले उपभोक्ताओं से रसोई गैस सिलिंडर पर मिलने वाली सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ने के लिए अपील कर चलाया था। सब्सिडी प्रणाली से बड़े स्तर पर एवं तेजी से लोगों को बाहर रखने का लक्ष्य प्रत्यक्ष सरकारी कदम के जरिये ही हासिल किया गया है लेकिन मोदी ने लोगों से स्वैच्छिक रूप से सब्सिडी छोड़ने की अपील की और इसी के साथ यह भी कहा कि इससे बचाया गया धन नेक काम में लगाया जाएगा। मोदी ने कोरोना पर लगाम के लिए देशवासियों से 'जनता कर्फ्यू' में शामिल होने का आह्वान कर ऐसा दूसरा प्रयास किया है। यह आगे उठाए जाने वाले कदमों की शुरुआती निशानी हो सकती है। वैसे कोरोना संक्रमण पर काबू करने में लगे कर्मचारियों के सम्मान में पांच मिनट तक तालियां बजाने को कहना सुनने में अटपटा लगता है। आसन्न महामारी से निपटने में लगे लोगों के प्रति सम्मान जताने के दूसरे सार्थक तरीके भी हैं।

मतदाताओं के बीच पर्याप्त नैतिक बल रखने वाला नेता ही इस तरह का प्रयोग सफलता से लागू कर सकता है। सीमित अर्थों में यह हमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के कुछ पहलुओं की याद दिलाता है। माओत्से तुंग का चीन भी अपनी सामाजिक गोलबंदी के लिए जाना जाता था लेकिन उसमें जोर-जबरदस्ती का पहलू भी शामिल रहता था। इस तरह इसके दोधारी तलवार साबित होने का जोखिम भी है।

अजय मोहंती

मोंटेक के साथ आर्थिक नीति-निर्माण का सफर

चुनिंदा आर्थिक नीति-विशेषज्ञों में शुमार मोंटेक सिंह आहलूवालिया की नई किताब से आर्थिक नीतियों के बारे में रोचक जानकारियां सामने आती हैं। बता रहे हैं **शंकर आचार्य**

मोंटेक सिंह आहलूवालिया की बहुप्रतीक्षित किताब 'बैकस्टेज' पिछले महीने प्रकाशित हुई। इस किताब की शुरुआती पंक्तियों में मोंटेक कहते हैं कि यह कोई संस्मरण न होकर भारत का आर्थिक यात्रा-वृत्तांत है। उसी तरह की साफगोई के साथ मैं यह कह सकता हूं कि यह लेख कोई पुस्तक समीक्षा नहीं है बल्कि एक अहम एवं पढ़ी जाने लायक किताब पर मेरे कुछ विचार भर हैं।

मोंटेक पिछले 55 वर्षों से मेरे दोस्त हैं जिसकी शुरुआत 1960 के दशक में ऑक्सफर्ड में पढ़ाई के दौरान हुई थी। उसके बाद सत्तर के दशक में मैक नेमारा के विश्व बैंक में एक युवा पेशेवर के तौर पर हम आठ साल साथ रहे। बीसवीं सदी के अंतिम दो दशकों में हम 15 साल भारत सरकार का हिस्सा भी रहे जिनमें 1990 के दशक में शुरू हुए आर्थिक सुधार के साल भी शामिल हैं।

मोंटेक निस्संदेह प्रतिभाशाली एवं प्रतिबद्ध 'आर्थिक नीति-विशेषज्ञों' के एक छोटे समूह के अग्रणी सदस्य हैं जिन्होंने आजादी के बाद से भारत में आर्थिक नीति के पालन में आर्थिक विवेक का अंश शामिल कराने के लिए कड़ी मेहनत की है। राजनीति, नौकरशाही, मनोदशा और चौतरफा फैली आर्थिक निरक्षरता के चलते पैदा होने वाली चुनौतियों को दरकिनार करते हुए ये नीति-विशेषज्ञ ऐसा कर पाए हैं। इस ख्यातिलब्ध समूह में एल के झा, आई जी पटेल, मनमोहन सिंह, सी रंगराजन, विजय केलकर, विमल जालान और वाई वी रेड्डी के नाम भी शामिल हैं। नब्बे के दशक में आर्थिक सुधारों की संकल्पना से लेकर उनके सफल क्रियान्वयन तक में इस चुनिंदा समूह के दिग्गजों की किसी-न-किसी रूप में सरकार के भीतर अहम पदों पर मौजूदगी रही। प्राथमिक तौर पर कहा जा सकता है कि हमारी मौजूदा आर्थिक दुर्दशा का एक कारण पिछले कुछ वर्षों में इस सामर्थ्य एवं अनुभव वाले आर्थिक विशेषज्ञों के नीति-निर्माण से दूर रहना भी है। यह किताब पिछले 40 वर्षों में भारत की आर्थिक नीतियों का एक दिलचस्प ब्योरा देता है। इसे राष्ट्रीय स्तर के एक प्रमुख नीति-निर्माता के नजरिये से लिखा गया है जिसने असाधारण रूप से लंबी एवं उत्पादक पारी खेली थी। इस किताब में वृद्धि, वित्त एवं व्यापार के वृहद आयामों से लेकर कृषि, उद्योग, आधारभूत ढांचे, दूरसंचार, डिजिटल एवं सामाजिक सेवाओं जैसे तमाम अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन सबमें समान बात सुधारों की पहल है या हर पल बदलते राजनीतिक परिदृश्य, पुरानी सोच एवं विचारधारा और निहित स्वार्थों के जमीनी हालात के संदर्भ में कम-से-कम हालात बेहतर करने की कवायद है। कहानी को सजीव ढंग से, साफगोई और पूरी निष्ठा के साथ बयां किया गया है जिसमें हास्य एवं व्यंग्य का भी पुट है। इसमें कोई निंदा या गुस्से का भाव नहीं है। इस किताब को पढ़ने पर लेखक की विलक्षणता, उठाए गए मुद्दों पर उनकी महारत और वृद्धि एवं आर्थिक कल्याण को लेकर प्रतिबद्धता का भाव झलकता है। आर्थिक नियंत्रण के निष्क्रिय हो चुके उपायों को उदार बनाने और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत की उत्पादक संबद्धता को बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है।

इस किताब में दिए गए तमाम हास्यपूर्ण किस्सों में से उदाहरण के तौर पर मैं लोक सेवकों से संबंधित किस्से का उल्लेख करने से मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूं। जब वी पी सिंह ने दिसंबर 1989 में प्रधानमंत्री पद संभाला था तो बी जी देशमुख और मोंटेक को क्रमश: प्रमुख सचिव एवं विशेष सचिव के पदों पर बने रहने को कहा गया था। इस पर मोंटेक के मन में उपजी दुविधा को दूर करते हुए देशमुख ने कहा था, 'मोंटेक, दिल्ली ऐसा शहर है जहां कप बदलते हैं लेकिन चमचे नहीं।'

यह किताब 1980 के दशक में इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी के समय शुरू हुए विनियंत्रण एवं आधुनिकीकरण के उपायों के साथ शुरू होती है। मोंटेक राजीव के कार्यकाल में प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके आर्थिक सलाहकार थे। फिर कहानी 1991 की शुरुआत में पैदा हुए भुगतान संतुलन संकट से होकर नरसिंह राव एवं मनमोहन सिंह के दौर में शुरू हुए व्यापक आर्थिक नीतिगत बदलावों को समेटती है। मोंटेक ने उस समय रिकॉर्ड सात वर्षों तक वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव पद पर रहते हुए दूरगामी नीतिगत कदमों की रूपरेखा तय करने में एक केंद्रीय एवं अपरिहार्य भूमिका निभाई थी। संयुक्त मोर्चा के दो साल के गतिरोधक शासन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की अगुआई में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने सरकार बनाई थी और ढांचागत क्षेत्र, दूरसंचार, निजीकरण, बीमा, अप्रत्यक्ष कर एवं राजकोषीय जवाबदेही से संबंधित नीतियों में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर सुधारों को आगे बढ़ाने का काम किया।

फिर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की साझा अगुआई वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) का एक दशक लंबा दौर आया जिसमें मोंटेक ने योजना आयोग की कमान संभाली थी। इस अवधि में आर्थिक नीतियों के निर्माण का उनका ब्योरा कुछ मायनों में शायद अधिक प्रशंसात्मक है। वह 2003-11 की अवधि में भारत की आठ फीसदी से ऊपर की आर्थिक वृद्धि और उसके चलते गरीबों की संख्या में आई गिरावट का सारा श्रेय तत्कालीन सरकार को ही देते नजर आते हैं। यह उत्पादकता बढ़ाने वाले सुधारों की दिशा में संप्रग के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए थोड़ा अनुचित लगता है। दूसरे लेखकों का भी मानना है कि संप्रग के सत्ता में आने के एक साल पहले ही शुरू हुआ यह उल्लेखनीय वृद्धि चक्र 1991 से लेकर 2004 के दौरान उठाए गए तमाम आर्थिक सुधारों का साझा परिणाम था। इसमें 2002-07 के दौरान की मजबूत वैश्विक आर्थिक वृद्धि का भी योगदान था जिसने कई अन्य विकासशील देशों की किस्मत को भी बदला था। टी एन नाइनन ने भी बिज़नेस स्टैंडर्ड के अपने साप्ताहिक स्तंभ में दुनिया एवं भारत के आर्थिक प्रदर्शन के बीच इस अंतर्संबंध को रेखांकित किया है। भारत वैश्विक आर्थिक संकट के दो साल बाद तक उच्च आर्थिक वृद्धि करता रहा था जिसमें 2009 के आम चुनाव के पहले किए गए भारी-भरकम राजकोषीय व्यय की बड़ी भूमिका थी लेकिन यह पांच वर्षों तक दो अंकों वाली उपभोक्ता मुद्रास्फीति और रिकॉर्ड बाह्य क्षेत्र घाटे की कीमत पर हुआ था।

लेख का समापन मैं आर्थिक नीति-निर्माण के इस दिग्गज शिल्पकार से जुड़े व्यक्तिगत संस्मरण से करना चाहूंगा। मैं कुछ समय विदेश में बिताने के बाद 1993 की शुरुआत में परिवार के साथ दिल्ली लौटा था और मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। सरकारी आवास मिलने के कुछ दिनों बाद ही मेरे बरामदे से होकर गुजरने वाली पानी की पाइप लीक होने लगी थी। सरकारी आवासों की देखरेख से संबंधित सीपीडब्ल्यूडी के नियमों से अनजान होने से मैंने सीधे मोंटेक को फोन लगाया और उनसे एक प्लंबर का इंतजाम करने के बारे में सलाह मांगी। उसके 15 मिनट के भीतर खुद केंद्रीय वित्त सचिव मेरे घर पहुंच चुके थे और पानी का रिसाव रोकने के इंतजाम में लग गए। उन्होंने फौरन एक पेड़ की छोटी टहनी काटी और उसे नुकीला बनाकर पाइप के छेद में घुसाकर रिसाव रोक दिया। इस घटना से दो बातें एकदम साफ हो गई थीं: मेरे विभाग के मुखिया को अपना काम बखूबी पता था और वह किसी भी हद तक मेरा साथ देने वाले थे। बाकी सब मजेदार होने वाला था और ऐसा ही हुआ।

(लेखक इक्रियर में मानद प्रोफेसर और भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

तमिलनाडु की राजनीति में असरदार होंगे रजनी-कमल?

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

अभिनेता से नेता बन चुके रजनीकांत ने 31 दिसंबर, 2017 को घोषणा की थी कि वह राजनीति में कदम रखेंगे। सवाल यह था कि सियासत में उनके प्रवेश का जरिया क्या होगा? अभी तक रजनीकांत अपने प्रशंसकों के क्लबों के लिए एक वेबसाइट एवं मोबाइल ऐप लेकर आए हैं। अभी तक तीन लाख से अधिक लोग इस वेबसाइट पर पंजीकरण करा चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये लोग उनके कट्टर समर्थक हैं। रजनीकांत का नारा क्या है? 'अच्छा करो और बोलो, आपके साथ भी अच्छा होगा।' लोग अब भी उनके राजनीतिक दल के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। इस दल का राजनीतिक मकसद क्या है? द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) को हराना।

यही वजह है कि इस महीने की शुरुआत में रजनीकांत की एक प्रेस सभा को लेकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह था। हरेक ने सोचा कि इस सभा में ही वह अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन इस संवाददाता सम्मेलन में कुछ खास हुआ नहीं, केवल रोजमर्रा की सियासी बातें होती रहीं। हमें अब यह सुनने को मिल रहा है कि अप्रैल में इस पार्टी का ऐलान होगा।

साफ कहें तो समय बीतता जा रहा है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव मई 2021 में होने वाले हैं। कमल हासन की मक्कल निधि मैयम (एमएनएम) और टीटीवी दिनकरन की अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कषगम (एएमएमके) जैसे नए दल पहले से ही मौजूद हैं। सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के रिश्ते यूं तो सहयोगियों की तरह हैं लेकिन दोनों दलों के शीर्ष नेताओं के एक-दूसरे के खिलाफ विष-वमन से हालात असहज हो चुके हैं। वैसे दोनों दल आधिकारिक तौर पर यही कह रहे हैं कि इन नेताओं की टिप्पणी से उनका सरोकार नहीं है। एक महीने पहले तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहने के बाद राज्य के मंत्री डी जयकुमार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता पोन राधाकृष्णन के एक बयान की आलोचना की थी। राधाकृष्णन ने कहा था कि तमिलनाडु-केरल सीमा पर तैनात स्पेशल सब-इंस्पेक्टर वाई विल्सन की संदिग्ध आईएसआईएस तत्त्वों द्वारा की गई हत्या राज्य के एक आतंकी ठिकाना बनने की निशानी है। जयकुमार ने कहा कि पोन राधाकृष्णन ने वाजपेयी सरकार में मंत्री रहते हुए तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया था। इस तरह दोनों दलों के बीच कहासुनी शुरू हो चुकी है और चतुर दल इसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेगा।

ऐसे हालात में रजनीकांत को तेजी से कदम उठाने होंगे। अभी तक उन्होंने जातीय एवं नागरिकता से तटस्थ तरीके से अपनी बात रखी है। हालांकि उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के आलोचकों के खिलाफ खुलकर सामने आते हुए कहा था कि यह कानून अल्पसंख्यक-विरोधी नहीं है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने इस्लामी समुदाय के नेता के साथ मुलाकात के लिए सहमति जताकर चेन्नई में सीएए प्रदर्शनकारियों को संकेत दे दिया था। वह चाहते हैं कि उनकी पार्टी भ्रष्टाचार खत्म करने और सुशासन के लिए काम करे। जिस राज्य में राजनीति पर दबदबा हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान पर हमला करने वालों का रहा है, रजनीकांत का दखल महज बयानबाजी से अधिक होना होगा।

इसके समानांतर एक और रोचक घटनाक्रम है। तमिलसाई सुंदरराजन को छह महीने पहले तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद एल मुरुगन को तमिलनाडु में भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पेशे से वकील और आरएसएस के सक्रिय सदस्य मुरुगन इसके पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष थे। वह अरुंधतीयार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं जो तमिलनाडु की आबादी में महज 3.7 फीसदी हिस्सेदारी होने के बावजूद राजनीतिक रूप से असरदार है। मुरुगन के पास दोहरा नुकसान है। वह ऐसे राज्य में एक दलित राजनीतिक नेता हैं जिसमें बेहद सक्रिय दलित नेता रहे हैं। इसके अलावा वह एक ऐसी पार्टी के दलित नेता हैं जो राज्य की परंपरागत तौर पर हिंदू-विरोधी रहने वाली राजनीति में खुद को स्थापित भी नहीं कर पाई है।

तमिलनाडु की राजनीति में मुरुगन की नियुक्ति का फौरन पड़ने वाले असर को लेकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। लेकिन इससे तमिलनाडु में भाजपा की भावी दिशा का अंदाजा जरूर लगता है। मसलन, क्या योगी आदित्यनाथ के चुनावी अभियानों के लिए यह राज्य तैयार है? भाजपा और रजनीकांत के बीच किस तरह का रिश्ता होगा? अगर रजनीकांत की सियासत का मकसद आगे भी द्रमुक को हराना ही रहता है तो इसके लिए सबसे अच्छा दांव अन्नाद्रमुक ही होगी। लेकिन रजनी तो अन्नाद्रमुक को भी हराना चाहते हैं।

यह बात रजनीकांत को भाजपा के लिए स्वाभाविक रूप से कारगर बना देती है। लेकिन भाजपा ने एक ऐसे व्यक्ति को मुखिया बनाया है जिसका राजनीतिक संवाद-कौशल अभी तक परखा ही नहीं गया है। दो बातें संभव हैं: मुरुगन गंभीर कार्यों का रिकॉर्ड रखने के बावजूद महज नाममात्र के नेता ही बनकर रह जाएं और तमिलनाडु में भाजपा के विकास से जुड़े फैसले कहीं और लिए जाएं। या फिर द्रमुक-विरोधी रुझान की स्थिति में मत भाजपा एवं अन्नाद्रमुक के बीच बंटने के बजाय तीन या चार हिस्सों में बंट जाएं।

आर के नगर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार को नोटा श्रेणी को मिले मत से थोड़े ही ज्यादा मत मिले थे। अक्टूबर 2019 में हुए दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव में तो भाजपा खड़ी ही नहीं हुई थी।

क्या तमिलनाडु राजनीति में द्रविड़-पश्चात दौर की तरफ बढ़ रहा है जहां रजनीकांत राजनीति में अध्यात्म की बातें कर रहे हैं और अच्छा बोलने एवं करने से अच्छा होने की धारणा में यकीन कर रहे हैं? वहीं भाजपा जमीनी स्तर पर काम करने में जुटी हुई है।

कानाफूसी

स्थिर या अस्थिर सरकार?

कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को यकीन है कि कांग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) के 11 विधायकों की भाजपा के टिकट पर जीत और उनमें से 10 को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से प्रदेश की बीएस येदियुरप्पा सरकार को जरूरी स्थिरता हासिल हो गई है। हालांकि ऐसा करने से पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और वफादारों में नाराजगी भी पैदा हो गई है। इस बीच विपक्ष की ओर से भी लगातार आलोचना सुनने को मिल रही है। विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने गुरुवार को मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से पूछा कि उनकी सरकार कितनी टिकाऊ है। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाजपा सरकार अगले तीन साल चलेगी या नहीं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि हम सत्ता में बने रहेंगे। इस पर सिद्धरमैया ने कहा कि अगर वह सत्ता में बने रहेंगे तो इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि वह सत्ता में बने ही रहेंगे। सिद्धरमैया ने इशारा किया कि खुद सत्ताधारी दल में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है।

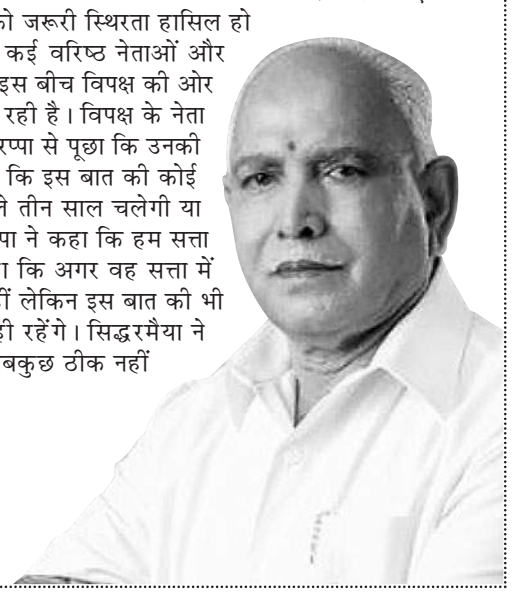

आपका पक्ष

समझें जनता कर्फ्यू का सही मतलब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस से निपटने के लिए एक उपाय यह दिया है कि 22 मार्च, 2020 को देश में जनता कर्फ्यू होना चाहिए। कुछ लोगों ने इसका उचित अर्थ न समझते हुए रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली चीजों की जमाखोरी करनी शुरू कर दी, जबकि जनता कर्फ्यू का मतलब यह है कि जनता स्वयं पर रोक लगाए। इसके लिए पुलिस या सुरक्षाबलों की तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। लोग खुद ही अपने काम टालें और घरों से बाहर निकलने से बचें तथा जो लोग आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, वे लोग ही काम के लिए बाहर निकलें। केंद्र और राज्य सरकारों ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए कुछेक व्यापारिक संस्थान भी बंद करने के आदेश दिए हैं।

दुकानें बंद होने की अफवाह के बीच जरूरी सामान की खरीदारी करते लोग। *फोटो: दलीप कुमार*

कुछ जगह सब्जी मंडियों के खोलने-बंद करने के नए नियम लागू किए गए हैं। लेकिन ऐसे सरकारी फरमानों से जहां एक ओर लोगों में घबराहट पैदा हो गई और बहुत-से लोगों ने खाद्य पदार्थों की जमाखोरी करनी शुरू कर दी, वहीं दूसरी ओर कुछ व्यापारियों ने कई वस्तुओं के दामों में कई गुणा बढ़ोतरी कर दी है, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि हमारे देश में खाद्य पदार्थों, सब्जियों आदि की कोई कमी नहीं है। सरकार को कोरोना से निपटने के साथ इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि लोगों को रोजमर्रा की चीजें प्राप्त करने में कोई परेशानी न उठानी पड़ी और न ही खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ें। सरकारों को चाहिए कि वह लोगों के घरों तक जरूरी सामान पहुंचाने का भी इंतजाम करे।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मिलकर करें कोरोना से मुकाबला

चीन से आ रही खबरों के मुताबिक कोरोना के नए मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है, लेकिन भारत में पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखते ही देखते यह संख्या 200 से ज्यादा तक पहुंच चुकी है। कई राज्यों में अब भी नए मामले सामने आ रहे हैं। अगले कुछ हफ्ते देशवासियों को धैर्य और संयम से काम लेना होगा। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए शब्द जनता कर्फ्यू को हमें गंभीरता से लेना होगा। रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का यह सुझाव हर नागरिक को मानना चाहिए। चीन के वुहान से आए एक वीडियो में अन्य प्रांतों से आए डॉक्टर और नर्सों के जत्थे को पुलिस और वहां के लोग सैल्यूट करते दिख रहे हैं। महीनों तक उनके परिश्रम को सम्मान देने का यह सबसे सहज तरीका है, जो हमें भी अपनाना चाहिए। सामाजिक दूरी के फार्मूले को फौरन अपनाना चाहिए। सोशल मीडिया पर ऐसे ही संदेश साझे करने चाहिए।

उद्देश कुमार, मणिपाल

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

सरकार पर बढ़ा संसद का मौजूदा सत्र रोकने का दबाव

अर्चिस मोहन

कोरोनावायरस के संक्रमण के संदेह में कई राजनीतिज्ञों के एकांतवास में जाने से सरकार पर संसद का मौजूदा सत्र रोकने का का दबाव बढ़ गया है। संसद का बजट सत्र आगामी 3 अप्रैल को खत्म हो रहा है और कई महत्त्पूर्ण विधेयक पारित होने शेष हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के ट्वीट के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। वसुंधरा ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्होंने और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह ने पिछले सप्ताह लखनऊ में पार्श्व गायिका कणिका कपूर की पार्टी में शामिल होने के बाद अपने को अलग-थलग कर लिया है। हालांकि वसुंधरा एवं उनके पुत्र दुष्यंत की जांच फिलहाल नहीं हुई है।

यह पूरा वाकया तब शुरू हुआ जब कणिका ने कहा कि उनमें कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है। ये दोनों नेता लखनऊ में कणिका की पार्टी में शामिल हुए थे। 41 वर्षीय कणिका ने इंस्ट्राग्राम पर जारी एक बयान में कहा कि पिछले चार दिनों से उनमें फ्लू के लक्षण पाए गए थे। कणिका ने कहा कि उन्होंने स्वयं को एकांतवास में रखा है। वह मार्च के दूसरे सप्ताह में लंदन से लखनऊ आई थीं। 14 मार्च से 16 मार्च के बीच उन्होंने कम से कम चार पार्टी में गई थीं और कानपुर में अपने परिवार के साथ भी समय गुजारा था। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कणिका जब लखनऊ हवाईअड्डे पर उतरीं तो उनकी जांच नहीं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह की जांच हो रही है, जबकि उनसे गुरुवार को मिलने वाले तीन विधायक खुद को अलग-थलग रख रहे हैं।

वसुंधरा और दुष्यंत सहित कई दूसरे राजनीतिज्ञ एवं अधिकारी लखनऊ के एक होटल में 13 मार्च को पार्टी में शामिल हुए थे। इस पार्टी में उत्तर प्रदेश

- वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह ने कणिका कपूर की पार्टी में की थी शिरकत
- कणिका में पाया गया है कोविड-19 का संक्रमण
- वह मार्च के दूसरे सप्ताह में लंदन से आई थीं
- दुष्यंत ने पार्टी में शामिल होने के बाद संसद की कार्यवाही में लिया था भाग
- कई दूसरे नेताओं के संपर्क में भी रहे थे

के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने अब अपने आप को एकांतवास में रखा है। दुष्यंत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोक सभा सदस्य हैं और लखनऊ से आने के बाद उन्होंने सक्रिय रूप से संसद की कार्यवाही और अन्य बैठकों में हिस्सा लिया था। बुधवार को वह उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के 100 सांसदों के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ एक बैठक में उपस्थित थे। राष्ट्रपति कार्यालय से ट्वीट किए उस कार्यक्रम की तस्वीरों में दुष्यंत राष्ट्रपति के ठीक पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। बाद में उसी दिन दुष्यंत ने परिवहन, विमानन एवं संस्कृति पर संसद की स्थायी समिति की बैठक में हिस्सा लिया था। एक दर्जन से अधिक सांसद और अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे। गुरुवार को वह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक पार्टी में शामिल हुए थे, जिसमें कई दूसरे सांसद भी मौजूद थे।

लखनऊ से लौटने पर दुष्यंत के साथ जिन लोगों ने बातचीत की थी, उनमें तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन और अपना दल की अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने भी स्वयं को एकांतवास में रखा है, क्योंकि वह डेरेक संपर्क में आए थे और उनसे बातचीत की थी। वसुंधरा ने अपने ट्वीट में कहा, 'लखनऊ में मैं अपने पुत्र दुष्यंत एवं अन्य संबंधियों के साथ पार्टी में शामिल हुई थी। कणिका भी उस पार्टी में शामिल थीं। एहतिहात बरतते हुए मैंने और दुष्यंत ने स्वयं को सबसे अलग कर लिया है। हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं।' तृणमूल नेता डेरेक ने कहा, 'यह सरकार हम सभी को जोखिम में डाल रही है। प्रधानमंत्री ने सभी को घरों में रहने के लिए कहा है, लेकिन संसद चल रहा है। मैं दूसरे दिन दुष्यंत के पास ढ़ाई घंटे तक बैठा था। दो अन्य सांसद भी एकांतवास में चले गए हैं। संसद का मौजूदा सत्र यहीं रोक देना चाहिए।' सूत्रों ने कहा कि दुष्यंत विपक्ष के एक नेता द्वारा आयोजित पार्टी में भी शामिल हुए थे। डेरेक संसद की स्थायी समिति की बैठक में दुष्यंत के बगल में करीब ढाई घंटे तक बैठे थे।

'कोलकाता को कोरोना से बचाएगी देवी काली'

अभिषेक रक्षित

ऐसा लगता है कि कोरोनावायरस फैलने के मद्देनजर जारी जन स्वास्थ्य परामर्शों की बड़ाबाजार में अनदेखी की जा रही है। बड़ाबाजार कोलकाता के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक है। यहां भीड़ पहले जितनी ही है। गलियों में विक्रेताओं की संख्या और शोर-शराबा भी पहले जितना ही है। ऐसा लगता है कि कुछ होम गार्ड और नागरिक स्वयंसेवियों के अलावा कोई भी इस बात से चिंतित नहीं है कि घातक और अत्यधिक संक्रामक वायरस का खतरा बढ़ा रहा है, जिससे लाखों संक्रमित और हजारों मर चुके हैं। हालांकि शेष कोलकाता में गलियां और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुक्रवार को तुलनात्मक रूप से खाली थे। लेकिन मध्य कोलकाता का बड़ाबाजार में कारोबार पहले के समान ही नजर आया। बड़ाबाजार में करीब 1,000 पंजीकृत और गैर-पंजीकृत दुकानें हैं। यहां रोजाना 100 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन होता है। हालांकि यहां के बहुत से कारोबारियों का कहना है कि भीड़ के बावजूद कोरोनावायरस के फैलने के बाद कारोबार घटा है। उन्होंने कहा कि यहां भीड़भाड़ कारोबार की वजह से नहीं बल्कि कार्यालय जाने के लिए यहां से गुजरने वाले लोगों की वजह से है।

मा काली ट्रेडर्स के मालिक रंजीत सिंह अरोड़ा ने कहा, 'भारत में कोरोनावायरस के मामले सामने आने के बाद से हमारी बिक्री 90 फीसदी कम हो गई है। थोक और खुदरा कारोबार प्रभावित हुए हैं। अगर इस वायरस की वजह से राज्य में लोगों की मौत हुई तो कारोबार और घटेगा।'

कपड़ा कारोबारी शेखर सिंह भी उतने ही निराश नजर आए। उन्होंने कहा, 'मैं आम तौर पर रोजाना 150 मीटर कपड़ा बेचता था। लेकिन अब यह घटकर केवल 25 मीटर रह गया है। कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है।'

लेकिन इससे दुकानदारों का माल का स्टॉक करना नहीं थमा है, जो थोक बाजार से अपना माल खरीदते हैं। बापी तुलाकदार ने कहा, 'किसी डर के कारण स्टॉक नहीं करना उचित नहीं है। इस समय कारोबार कम है, लेकिन मुझे उस समय के लिए तैयारी करनी है जब यह सुधरेगा।'

कुछ कारोबारियों ने कहा कि लोग आगे स्थितियां बिगड़ने के डर से खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार में हड़बड़ी नजर आ रही है। औद्योगिक

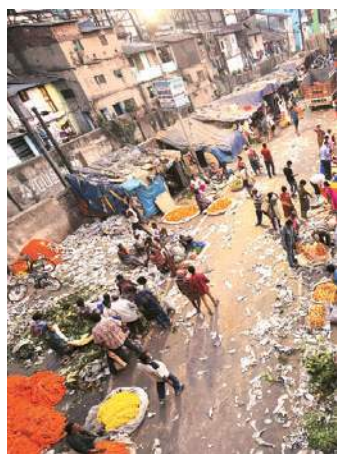

कोरोनावायरस के कारण कोलकाता में फूलों के थोक बाजार में कम विक्रेता आए नजर *पीटीआई*

पॉलिमर, प्लास्टिक तिरपाल बेचने वाली इंडिया कैनवास कंपनी के शंकर अग्रवाल ने कहा कि कुछ लोग इस अनिश्चितता के कारण स्टॉक कर रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा। हालांकि बहुत से कारोबारियों ने यह स्वीकार किया कि कोविड-19 की वजह से उनका कारोबार प्रभावित हुआ है। लेकिन वे यह नहीं मानते हैं कि भारी भीड़ उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है। गुटखे को थूकते हुए एक मेटल कारोबारी ने कहा, 'कोलकाता मां काली की जमीन है। वह रक्षा करेंगी, भले ही किसी भी वायरस का हमला हो।' साफ तौर पर उन्हें इस बात का पता नहीं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वायरस को नियंत्रित करने के एक उपाय के रूप में लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने को कहा है। मोस्ट होली रोजरी के कैथेड्रल के नजदीक एक स्ट्रीट वेंडर 60 रुपये की दर पर सिंगल यूज मास्क बेच रहा था। हालांकि यहां कारोबारी एक स्वर में बाजार को बंद करने के किसी कदम का विरोध करते हैं।

कपड़ा कोराबारी सिंह ने कहा, 'यह अमीरों की बीमारी है और यहां अमीर लोग खरीदारी करने नहीं आते हैं।' अग्रवाल ने पूछा, 'अगर दुकानें बंद रहीं और कोई कारोबार नहीं हुआ तो हम क्या खाएंगे?' दुकानदारों का कहना है कि केंद्र के भारत में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगाने के बाद बांग्लादेशी ग्राहक गायब हो गए हैं, जिनकी कुल ग्राहकों में करीब 40 फीसदी तादाद होती थी।

दिल्ली में कारोबार पर कोरोना का खौफ

पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले 6.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कारोबारियों को सता रहा है नुकसान का डर

शुभायन चक्रवर्ती

पुरानी दिल्ली की संकरी गलियों और यातायात जाम को देखते हुए लोगों से एक मीटर की दूरी बनाए रखना असंभव लगता है और निवासियों को इस बात पर संदेह है कि नगर निगम के अधिकारी इसको लेकर विज्ञापन करने की जहमत भी उठाएंगे। हल्के हाइड्रॉलिक मशीन के डीलरों को बेचने के लिए मैकेनिकल पार्ट्स तैयार करने की दुकान चला रहे प्रकाश अग्रवाल कहते हैं, 'क्या नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल कभी चावड़ी बाजार आते हैं? इन खराब सड़कों पर चलने की जगह तक नहीं बची है, हजारों लोग एक-दूसरे को झटका देते हुए चलते हैं।'

अग्रवाल की 43 साल पुरानी दुकान 150 साल पुरानी गली घासी राम लेन पर स्थित है जहां रहने वाले काम करते हैं और बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। यहां सभी बिना मास्क के नजर आते हैं और वे कोरोनावायरस की फैलती दहशत से भी अनजान दिखते हैं। पंप सेट के थोक विक्रेता और अग्रवाल के पड़ोसी अफजल शेख कहते हैं, 'पिछले साल से कारोबार मंदा है और अब हम ऑर्डर रद्द कर रहे हैं। मुझे आशंका है कि कोरोनावायरस की वजह से चीजें और खराब होंगी।'

पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले 6.1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मौजूद ज्यादातर कारोबारियों में भ्रम वाली स्थिति से जूझ रहे हैं और उन्हें नुकसान का डर भी सता रहा है। कम से कम एक दर्जन उद्योगों के माल का यह प्रमुख वितरण केंद्र है और आधुनिक दिल्ली का यह मुख्य क्षेत्र अभी तक बंद नहीं हुआ है।

अमूमन भारी भीड़ वाले चावड़ी बाजार से ग्राहक हुए नदारद

लोहे के पाइप आदि के खुदरा विक्रेता सुधीर जैन कहते हैं, 'यहां भी सबकुछ जल्द बंद हो सकता है। मार्केट एसोसिएशन ने 21 मार्च से पूर्ण बंद का आह्वान किया है। अगर वे दुकान बंद कर देते हैं तो मुझे काफी मुश्किल आएगी क्योंकि भंडार का ज्यादातर माल बेचा नहीं गया है और आपूर्तिकर्ता भुगतान को लेकर चिंतित हो रहे हैं।'

हौज काजी की खाली गलियों में जैन कहते हैं, 'दिल्ली में लोग पुराने तरीके से कारोबार करना पसंद करते हैं । यहां तक कि पुराने खरीदार जो हमारे उत्पादों पर भरोसा करते हैं, वे मिलने आते हैं और ऑर्डर पर खुद ही हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन अब ज्यादातर वायरस के कारण अपनी यात्राएं रद्द कर रहे हैं।'

देश में सूखे मेवे और मसालों के सबसे बड़े बाजार खरी बावली में मौजूद दुकानदार इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि व्यक्तिगत स्पर्श को कैसे रोका जाए। सूखे मेवे के एक कारोबारी भजन राम कहते हैं, लोग आमतौर पर मेवे को चखकर उसका स्वाद लेने के लिए थोड़ा सा उठाते हैं। लेकिन मैं यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि वे सभी अपने हाथ धोएं।'

सुनसान बाजार

पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय परिधान बाजार लक्ष्मीनगर में सड़कें खाली-खाली सी दिख रही हैं। ओसवाल फैशन शोरूम में शॉप मैनेजर बलराम कहते हैं, 'हमारे जैसे खुदरा विक्रेताओं के लिए हालात और भी खराब होंगे जब ग्राहक घर से बाहर कदम नहीं रखते हैं। आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है और अब लोग गांव वापस जा रहे हैं तब मजदूरी की लागत भी बढ़ रही है। साल के इस समय हमारा रोजाना कारोबार 1.8 से 2 लाख रुपये तक का होता था जो कम होकर 45,000 तक हो गया है।' छोटे कारोबारियों के लिए हालात और भी खराब है। 62 वर्षीय अश्विनी कुमार निराशा के साथ कहते हैं, 'लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी दुकान न खोलूं या आप संक्रमित हो जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब मैं अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता।' उनकी दुकान की दीवार पर चमड़े के बैग, बेल्ट और पर्स लटके हुए हैं क्योंकि खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। सड़कों पर अफवाहों और वाट्सएप फॉरवर्ड का असर नफीज के कारोबार पर दबाव बना रहा है। उनके 12 साल पुराने कसाईखाना कलकत्ता मीट शॉप पर संकट के बादल छाए हुए हैं। वह थके हारे अंदाज में अपनी खाली दुकान को देखते हुए कहते हैं, 'लोग ऐसे समय में मांसाहारी भोजन से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब डॉक्टरों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि चिकन का सेवन करने से कोरोनावायरस नहीं होता। लेकिन लोग सुन नहीं रहे हैं।'

पार्टी भी बंद

नई दिल्ली के मशहूर कनॉट प्लेस के पॉश इलाके में राज्य सरकार के आदेश की वजह से सभी फूड और बेवरिज कारोबार बंद हैं जिससे यहां निराशा की स्थिति दिख रही है। एक मशहूर बार के गेट के बाहर निगरानी के लिए खड़े रविंद्र ने बताया, 'पुलिसकर्मियों ने सभी बार और नाइटक्लब का दौरा करना शुरू कर दिया है और वे इन्हें बंद करने का आदेश दे रहे हैं। अगर यह जगह अगले 10 दिन तक बंद रहती है तब हममें से कम से कम 5 लोग जिन्हें साप्ताहिक आधार पर भुगतान किया जाता है उनके पास नौकरी नहीं रहेगी।' निजी क्षेत्र के दफ्तरों में काम करने वाले लोग अब घर से काम करने लगे हैं ऐसे में उनके पास अब पर्याप्त वक्त होता है जिसकी वजह से यहां लोग ठीक तादाद में आ रहे थे। 23 साल की प्रज्ञा सैनी संदेह भरे अंदाज में कहती हैं, 'मैं एक लॉ कंपनी में हफ्ते में छह दिन काम करती हूं। मैंने दिन का काम घर से पूरा किया है और मेरे लिए यह काफी मुश्किल होता है कि मैं अपने खाली वक्त का लुत्फ भी न उठाऊं।'

मुंबई में कारोबारी गतिविधियों पर लगा ताला

राजेश भयानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में जनता कर्फ्यू के आग्रह से पहले ही मुंबई ने कोरोनावायरस के खतरे को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और एक हफ्ते से ही यहां यातायात में कमी दिख रही है और सार्वजनिक परिवहन के यात्रियों की तादाद भी घटी है। ज्यादातर दफ्तरों खासतौर पर संगठित क्षेत्र के दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। कुछ जरूरी चीजों को छोड़कर मॉल भी बंद हैं और सड़क पर सामान बेचने वाले वेंडर भी नजर नहीं आ रहे हैं। मुंबई की खाऊ गली का क्षेत्र भी खाली है। पार्क और समुद्र के तट भी खाली हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार ने कुछ जरूरी जिंसों की बिक्री वाले दुकानों और वित्तीय बाजारों को छोड़कर 31 मार्च तक सभी कार्यस्थलों को बंद करने का फैसला लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि शहर के एक बड़े हिस्से में कम गतिविधियां होंगी।

दक्षिण मुंबई के 5 वर्गकिलोमीटर के दायरे में फैला सी-वॉर्ड कई खुदरा और थोक बाजारों का केंद्र है मसलन आभूषण के लिए जवेरी, इलेक्ट्रिक सामानों के लिए लोहार चॉल और कपड़े के लिए मुल्जी जेठा बाजार आदि। यहां का क्षेत्र भीड़ से भरा है और सैकड़ों हजारों लोगों में कारोबारी, ग्राहक और कर्मचारी शामिल हैं। गुरुवार तक इनमें से कई बाजार खुले थे लेकिन ग्राहक यहां मौजूद नहीं थे। शुक्रवार को ज्यादातर दुकानें बंद हैं और सड़कें खाली हैं।

गुरुवार तक स्थानीय अधिकारियों ने लोगों की भीड़ कम करने की कोशिश की लेकिन अब कारोबारी परिसर पूरी तरह बंद हो चुके हैं जिनमें थोक और मुंबई का खुदरा बाजार शामिल है।

मुंबई के लोहार चोल में पसरा सन्नाट फोटो : कमलेश पेडणेकर

हालांकि कुछ बाजारों ने सरकार के दिशानिर्देशों पर ध्यान नहीं दिया और कारोबार जारी रखा। थोक फूड बाजार कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) वाशी को गुरुवार को बंद रखा गया ताकि कीटाणुनाशक डाला जाए और वहां लोगों को कोरोनावायरस से सुरक्षा दे पाएंगे। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और ओपरा हाउस में हीरा कारोबारियों ने भारत डायमंड बोर्स से भीड़ हटाने की कोशिश की। इन बाजारों में मजदूरी करने वाले लोगों की तादाद कम हो गई है। करीब 10,000-12,000 लोग अनुमानत: सी वॉर्ड में ही काम करते हैं जिनमें से ज्यादातर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के गांवों में चले गए हैं।

दिल्ली में गैर-जरूरी सेवाएं 31 मार्च तक स्थगित

पृष्ठ 1 का शेष

पंजाब सरकार ने शुक्रवार रात से सार्वजनिक परिवहन को बंद करने का फैसला किया है। राज्य में बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं और 20 या उससे अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने पर पाबंदी लगा दी गई है। हालांकि टैक्सी को इस बंद से अलग रखा गया है। ओला और उबर के भी रविवार को अपनी सेवाएं बंद रखने की उम्मीद है। उत्तराखंड सरकार ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के राज्य में प्रवेश पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है।

दिल्ली सरकार ने अपनी सभी गैर-जरूरी सेवाओं को 31 मार्च तक स्थगित करने और ऐसे विभागों के कर्मचारियों को घर से ही काम करने की अनुमति देने की घोषणा की है रेलवे ने यात्रियों की कम संख्या और कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर 20 से 31 मार्च के बीच चलने वाली 90 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही रद्द की गईं ट्रेनों की संख्या बढ़कर 245 हो गई है। इन ट्रेनों

विजयवाड़ा में नव विवाहित जोड़े की जांच

में टिकट रद्द होने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यात्रियों को पूरा पैसा वापस मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों को कोरोनावायरस के कारण स्कूल बंद रहने तक पात्र छात्रों को मध्याह्न भोजन या खाद्य सुरक्षा भत्ता मुहैया कराने की सलाह दी है। इस बीच सेना ने कहा है कि सैन्य मुख्यालय में कार्यरत 35 फीसदी अधिकारी और 50 फीसदी जेसीओ 23 मार्च से एक सप्ताह के लिए घर से काम करेंगे।

इटली में मृतकों की संख्या चीन से ज्यादा हुई

कोरोनावायरस का कहर दुनियाभर में जारी है। इस वायरस से दुनिया भर में 2,34,000 से अधिक लोगों संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 9,700 से अधिक है।

यूरोप के विकट हालात

इटली में कोरोनावायरस से मरने वालों की संख्या चीन से ज्यादा हो चुकी है जहां यह वायरस पहली बार सामने आया था। पिछले 24 घंटे के दौरान इटली में कुल 427 मौतें दर्ज की गईं हैं। इस तरह 21 फरवरी को इसके प्रसार के बाद से देश में कुल 3,405 मौतें हो चुकी हैं।

स्पेन के अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर संक्रमण के मामलों के बाद नर्सिंग होम में कोरोनोवायरस से और मौतों को रोकने के लिए विशेष उपाय करने का वादा किया है। स्पेन में मरने वालों की संख्या 767 हो गई है। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को कोरोनोवायरस से 108 और मौतों की सूचना दी है जिसमें मरने वालों की कुल संख्या 372 हो गई है। इसमें लगभग 41 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। ग्रीस अपनी अर्थव्यवस्था की मदद के लिए 10 अरब यूरो डालने के लिए तैयार है। उसने गुरुवार को कोरोनोवायरस के 46 नए मामलों की पुष्टि की है जिससे वहां कुल मामले 464 हो गए हैं।

ब्रिटेन ने 20,000 सैन्य कर्मियों को तैयार रखा हुआ है। लंदन और क्वीन एलिजाबेथ के दर्जनों भूमिगत ट्रेन स्टेशन बंद करा दिए गए हैं।

सर्बिया ने गुरुवार को अपना हवाई अड्डा बंद कर दिया और कहा कि वह माल ढुलाई के अलावा सभी सड़क और रेल सीमाओं को बंद कर देगा, साथ ही सभी आंतरिक यात्री परिवहन भी रोक देगा।

यूरोपीय संघ के कुछ देशों द्वारा अपनी सीमाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों से खाद्य आपूर्ति बाधित हो रही है। उद्योग के प्रतिनिधियों और किसानों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है।

दुनियाभर में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,34,000 के पार

ब्रेक्जिट के लिए यूरोपीय संघ के मुख्य वार्ताकार मिशेल बार्नियर ने गुरुवार को कहा कि वे कोविड-19 की जांच में पॉजिटीव पाए गए हैं। जर्मनी और ब्रिटेन ने सैन्य कर्मियों को तैयार रखा हुआ है। इटली का वायरस से संक्रमित एक क्रूज दक्षिणी फ्रांस के मार्शेल पर रोका गया है। उसके 1,400 यात्री और चालक दल जांच का परिणाम आने तक बोर्ड पर ही रहेंगे। क्रोएशिया, उत्तरी आयरलैंड और रूस ने गुरुवार को अपने यहां पहली मौतों की सूचना दी है।

अमेरिका में स्थिति

कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गुरुवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शुक्रवार को अमेरिका-कनाडा सीमा बंद हो जाएगी। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने गुरुवार को 10,491 मामले दर्ज किए और कहा कि मरने वालों की संख्या 53 से बढ़कर 150 हो गई है जो एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें हैं। अगले आठ हफ्तों के दौरान कैलिफोर्निया में 60,000 से अधिक बेघर लोग संक्रमित हो सकते हैं।